सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh

Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

वर्ष 1, अंक 89, नई दिल्ली, गुरुवार, 26 जनवरी 2023, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

NEWS TRANSPORT VISHESH NTV
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के परेड की सलामी ली और तिरंगा

05 कई वेरिएंट्स बंद होने के बाद भी कायम है टाटा की इस कार का जलवा

08 जानिए राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की खास बातें

आज का सुविचार

वर्तमान को आग में झोंके बिना भविष्य का मार्ग प्रशस्त नहीं होता।

एनएच-9 से जुड़ेगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे, लाखों लोगों का सफर होगा आसान

उक्त मार्ग की दूरी करीब 25 किलोमीटर होगी। मार्ग का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड व कुछ हिस्सा भू-तल पर होगा।

संजय बाटला

नई दिल्ली। जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने कहा कि शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होने से विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। यह सारी कवायद गाजियाबाद के विकास को पंख लगाने के लिए की जा रही है। योजना के परवान चढ़ने से लाखों लोगों को राहत मिलेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। छिजारसी के पास से एनएच-9 को नार्दन पेरिफेरल व दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। उक्त मार्ग की दूरी करीब 25 किलोमीटर होगी। मार्ग का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड व कुछ हिस्सा भू-तल पर होगा।

एनएच-9 के दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के जुड़ने से लोग गाजियाबाद से ढाई घंटे में देहरादून पहुंच सकेंगे। कनेक्टिविटी बेहतर होने से एक तरफ जहां लोगों को सहूलियत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ विकास को पंख लगेंगे।

जीडीए के मुख्य अभियंता राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जीडीए के प्रस्ताव पर एनएचएआइ ने सर्वे के बाद उपरोक्त छह लेन का मार्ग बनाकर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यूपी इंवेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए आज कौशांबी स्थित रेडिशन ब्लू होटल में होने वाले जिला स्तरीय समिट में एनएचएआइ के अधिकारी उपरोक्त प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन देंगे।

इस प्रोजेक्ट से ऐसे मिलेगी राहत

एनएच-9 छिजारसी कट के पास से मार्ग शुरू होगा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के ऊपर से होते हुए हरनंदी नदी पर पुल के जरिये पार होगा। इसके बाद हरनंदी नदी व सिद्धार्थ विहार के बीच से होते हुए सांई उपवन, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास से होते हुए राजनगर एक्सटेंशन को जाने वाली सड़क में जुड़ेगा। वहां से करहैड़ा रोटरी को पार कर सिटी फारेस्ट से आगे एक बार फिर हरनंदी नदी को पुल के जरिए पार कर भनेड़ा खुर्द के पास नार्दन पेरिफेरल रोड में जुड़ेगा। यहां टीला मोड, निस्तौली व लोनी की तरफ जाने वाले लोग नार्दन पेरिफेरल रोड पर चढ़कर गंतव्य तक जा सकेंगे। वहीं जिन लोगों को देहरादून की तरफ जाना होगा। वह उक्त मार्ग पर नार्दन पेरिफेरल रोड को पार सीधे मंडोला के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर चढ़कर देहरादून जा सकेंगे।

भविष्य में एफएनजी से भी जुड़ेगा

फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद (एफएनजी) एक्सप्रेस-वे भी भविष्य में छिजारसी के पास उक्त मार्ग से जुड़ सकेगा। एफएनजी एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट जब भी पूरा होगा। उसके उक्त मार्ग से जोड़ने के लिए विकल्प रखा जाएगा। अभी फिलहाल ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के जरिये फरीदाबाद व पलवल के लोग डासना आएंगे। इसके बाद नार्दन पेरीफेरल रोड पर चढ़कर उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर पहुंच सकेंगे।

मंडोला में बनेगा बड़ा जंक्शन, लोनी का होगा विकास

जीडीए के मुख्य अभियंता ने बताया कि योजना के परवान चढ़ने पर लोनी स्थित मंडोला बड़ा जंक्शन बनेगा। इससे लोनी क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर जहां उपरोक्त मार्ग को जोड़ने की योजना है। वहीं एनएचएआइ की अरबन रोड की योजना है जो भविष्य में सीधे एयरपोर्ट को जाने वाले मार्ग से जुड़ेगी।

इनसाइड

गुरुग्राम बस डिपो को मिलेंगी 189 ई-टिकटिंग मशीन

गुरुग्राम। गुरुग्राम बस डिपो के परिचालक यात्रियों को टिकट पंचिंग कर नहीं देंगे, बल्कि एक बटन दबाते ही टिकट बाहर आएगा। गुरुग्राम की रोडवेज बसों में जल्द ही ई-टिकट की सुविधा शुरू हो जाएगी। शहर से हरियाणा के विभिन्न जिलों व दूसरे प्रदेशों में जाने वाली रोडवेज बसों सहित लोकल रूटों पर चलने वाली बसों के किलोमीटर व उसके अनुसार किराया तय किया जा रहा है। गुरुग्राम बस डिपो को 189 इलेक्ट्रानिक टिकटिंग मशीन (ईटीएम) मिलेंगी। डिपो के दो परिचालक मनोज व संदीप बतौर यातायात निरीक्षक (टीआई) ई-टिकटिंग मशीनों में किलोमीटर व किराए संबंधित जानकारी देने के लिए गए हुए हैं।

अब राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग को लेकर खड़ा हुआ नया विवाद

एनटीवी, दिल्ली। एसडी सेठी। धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम को लेकर इन दिनों चर्चा खासा जोरों पर है। ये -विवाद अभी थमा भी नहीं कि बागेश्वर धाम बाबा के गुरू जगद्गुरू रामभदराचारय ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग करके नया विवाद खडा कर दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के गुरू जगदगुरू रामभदराचारय ने कहा है कि जब तक भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल नहीं किया जाता है तो तब तक वो यहां पर अगली कथा करने नहीं आऐगें। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले ही राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग होने लगी है। ये मांग जगद्गुरू रामभदराचारय ने सी एम शिवराज सिंह चौहान से कथा के दौरान सामने पेश की । इस पर संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर ने आगे कहा कि जहां नाम बदलने की बात है वो तथ्यों और प्रमाण के हिसाब से ही बदला जाता है।यह सब संवैधनिक, दायरे में सत्य के आधारभूत तय किया जाता है।बता दें कि गुरू भद्राकाल जन्म से देख नहीं पाते हैं। बावजूद इसके उन्हें 36भाषाओं पर अधिकार है।उन्हें नैन सुख होने के बाद भी वेद पुराण, और रामायण कंठस्थ है।

इन 9 चीजों पर अगर किसी ने सड़क पर चलते समय अमल नहीं किया तो उसका 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा इसलिए हमेशा ट्रैफिक के नियम का पालन करें

संजय बाटला

नई दिल्ली। इन 9 चीजों पर अगर किसी ने सड़क पर चलते समय अमल नहीं किया तो उसका 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा इसलिए हमेशा ट्रैफिक के नियम का पालन करें।

1. गलत दिशा में ड्राइविंग ना करें
2. बिना हेलमेट ना चलें
3. बिना सीट बेल्ट पहने ना चलें
4. गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें
5. रेड लाइट पार बिल्कुल ना करें 6. कमर्शियल गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल की तरह इस्तेमाल बिल्कुल ना करें
7. अपनी गाड़ी में सवारियों को ना बैठने दे
8. शराब पीकर गाड़ी ड्राइविंग बिल्कुल ना करें
9. ओवर स्पीड में गाड़ी को बिल्कुल ना चलाएं।

अगर आप इनमें से किसी नियम का भी सड़क पर चलते समय पालन नहीं कर रहे तो ट्रैफिक पुलिस एवं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपका सड़क पर कहीं पर भी चालान काट सकता है और उसके साथ उसी चालान के आधार पर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है।

इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं आप हमेशा सड़क पर सावधानी से चलें और आप हमेशा ट्रैफिक के नियमों का पालन करें नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में 10 गुना जुर्माना लागू हो चुका है।

कृप्या आप सभी ट्रैफिक के नियमों की जानकारी अपने जानकारों एवं रिश्तेदारों को एवं अन्य सभी लोगों में यह जानकारी अवश्य शेयर करें।

अब जरूरी नहीं है आपको पुलिस सड़क पर

रोके अब आपका चालान सीसी टीवी के माध्यम से एवं पुलिस के सड़क पर फोटो खींचने से भी घर पर पोस्टल चालान के रुप में आ सकता है इसलिए सड़क पर सावधानी से चलें और सड़क पर गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें ।गलत दिशा में वाहन बिल्कुल ना खड़ा करें ट्रैफिक के नियमों का हमेशा ही पालन करें पुलिस एवं प्रशासन को हमेशा सहयोग करें क्योंकि वही आपके दुख सुख के साथी हैं। जय हिंद जय भारत।

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

दो पहिया चालक हेलमेट पुलिस को देखकर नहीं अपने परिवार को देखकर पहने । आप अगर अपने परिवार और शरीर से प्यार करते हैं तो हेलमेट अवश्य ही लगा कर चले । हेलमेट ना पहनने पर शारीरिक नुकसान के खतरे के अलावा जुर्माना और मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा।

आप सभी से सड़क सुरक्षा में सहयोग की आशा

संजय बाटला
अध्यक्ष टोलवा

गणतंत्र दिवस परेड के लिए डीटीसी बसों के 13 मार्ग बदले, सुबह चार बजे से बसों के चलने पर पाबंदी

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में विजय चौक से बृहस्पतिवार को गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होगी। कर्तव्य पथ-इंडिया गेट-प्रिंसेस प्लेस गोल चक्कर-तिलक मार्ग-से आगे बहादुर शाह जफर मार्ग-दिल्ली गेट-नेताजी सुभाष मार्ग से होकर परेड लाल किला पहुंचेगी। ऐसे में इन मार्गों पर सुबह चार बजे से ही बसों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के निर्देश के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम ने बसों के सुचारू संचालन के लिए इंतजाम किए हैं। इसके तहत विजय पथ, विजय चौक, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक ब्रिज क्षेत्र में वाहनों को सुबह चार बजे से दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। डीटीसी के 13 मार्ग परिवर्तित किए गए हैं।

इन मार्गों पर बसें की जाएंगी डायवर्ट

- शांति पथ से कनॉट सर्कस/नई दिल्ली रेलवे के लिए जाने वाली बसें पंचशील मार्ग, साइमन बोलिवर मार्ग, अपर रिज रोड, शंकर रोड गोल चक्कर, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड से होकर कनॉट सर्कस जाएंगी। लौटने के दौरान बसें भगत सिंह मार्ग, पेशवा रोड से जाएंगी। इससे 604, 620 और रूट नंबर 680 की सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
- विनय मार्ग-कनॉट प्लेस और नई दिल्ली जाने वाली बसों के रूट में भी बदलाव रहेगा। इस रूट की बसें भगत सिंह मार्ग और पेशवा रोड होकर लौटेंगी। रूट नंबर 781 की बसें परिवर्तित मार्ग पर चलेंगी।
- अरबिंदो मार्ग-लोधी रोड टी प्वाइंट और सफदरजंग रोड से आने जाने वाली बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। इसके लिए बस रूट संख्या 433, 460, 505 और 615 में बदलाव के बाद बसें भगत सिंह मार्ग, पेशवा रोड से होकर गुजरेंगी। अरबिंदो मार्ग से पूर्वी दिल्ली, आईएसबीटी, पुरानी दिल्ली रेलवे के लिए बसों को लोधी रोड टी-प्वाइंट पर मोड़ दिया जाएगा। इसके बाद बसें ओबेरॉय होटल, मथुरा रोड भैरो मार्ग, रिंग रोड आईटीओ फ्लाईओवर, आईजी स्टेडियम, वेलोड्रोम रोड, न्यू रिंग रोड यमुना नदी के समानांतर मोरी गेट तक दोनों दिशा-निर्देश और मोरी गेट पर समाप्त होगी।

लोगों में खुशी की लहर, जनपद प्रतिनिधि रविन्द्र कृष्णचंद्र सीसोदिया (ठाकूर) ने गुरुखेडी मे पानी की समस्या के चलते ट्युबवेल की दी सौगात

एनटीवी संवाददाता

रतलाम जिले की आलोट जनपद पंचायत अंतर्गत जनपद प्रतिनिधि रविन्द्र कृष्णचंद्र सीसोदिया ने अपने क्षेत्र का दौरा कीया, लोगो की समस्या सुनी। और पता चला की गांव गुरु खेडी मे पीने के पानी की समस्या है। लोगो को काफी दिक्कत आ रही है। इसी के चलते रविन्द्र सीसोदिया ने तुरंत प्रभावित होकर पीने के पानी के लीये गांव गुरु खेडी को ट्युबवेल की दी सौगात। क्षेत्र के लोगो मे खुशी की लहर ।लोग बोले हमने आज तक जनता की इतनी सेवा करने वाला जनपद प्रतिनिधि नही देखा जो दिन रात गावो के विकास कार्य मे लगा रेहता हो।

परेड के दौरान तिलक ब्रिज पर ट्रेनों की आवाजाही भी होगी बंद

रिपब्लिक डे पर ऐसी रहेगी दिल्ली में व्यवस्था

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। रिपब्लिक डे के लिए दिल्ली में पूरी तैयारी हो गई है। ट्रैफिक रूट, बस-मेट्रो के शेड्यूल से लेकर परेड स्थल जाने वालों के लिए एंट्री की व्यवस्था तक इंतजाम कर लिए गए हैं। परेड देखने वाले और आम लोगों को परेड के दौरान और बाद में किसी तरह की परेशानी न हो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। देखें कल दिल्ली में क्या रहेगी व्यवस्था।

गणतंत्र दिवस समारोह में करीब 65 हजार लोग शिरकत करेंगे। परेड स्थल के चैक पॉइंट पर पास व टिकट पर मौजूद क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा पहली बार किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के सुरक्षा इंतजामों को लेकर मंगलवार शाम को नई दिल्ली जिले के डीसीपी प्रणव तायल ने यह जानकारी प्रेस ब्रीफिंग में दी। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड स्कैन होते ही विजिटर की पूरी डिटेल सुरक्षाकर्मी के सामने होगी। सिर्फ पास व टिकट धारकों को ही परेड देखने के लिए एंट्री दी जाएगी। परेड स्थल के आसपास दिल्ली पुलिस के करीब 7 हजार जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा एनएसजी कमांडो, अर्धसैनिक बल और अन्य यूनिटों की मुस्तैदी रहेगी। समारोह स्थल व आसपास के इलाके को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। जिसकी कमान डीआरडीओ के हाथो में रहेगी।

डीसीपी ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर करीब 150 से अधिक अतिरिक्त हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो और वे सही एनक्लोजर से दर्शकस्थल के लिए एंट्री ले सकें। इसके लिए जगह-जगह 24 हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। 25 जनवरी की रात से ही कनॉट प्लेस व परेड रूट की हाई राइज इमारतों को सील कर दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं। उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हुए हैं।

परेड के दौरान तिलक ब्रिज पर ट्रेनों की आवाजाही भी होगी बंद

गणतंत्र दिवस परेड के लिए किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर 26 जनवरी की सुबह नई दिल्ली के तिलक ब्रिज पर ट्रेनों की आवाजाही भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी। नॉर्दर्न रेलवे ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया कि 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक सेवा प्रभावित रहेगी। इस दौरान 4 ट्रेनें रद्द की जाएंगी। इनमें नई दिल्ली-गाजियाबाद स्पेशल जेसीओ, पलवल-गाजियाबाद-पलवल स्पेशल जेसीओ, पलवल-नई दिल्ली स्पेशल जेसीओ और गाजियाबाद-नई दिल्ली स्पेशल जेसीओ शामिल हैं।

इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जाएंगे। नई दिल्ली-गाजियाबाद ईएमयू को नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली, शाहदरा और साहिबाबाद के रास्ते चलाया जाएगा। शकूरबस्ती-पलवल ईएमयू को पटेल नगर-सफदरजंग-हजरत निजामुद्दीन के रास्ते चलाया जाएगा। दिल्ली-गाजियाबाद स्पेशल (वाया तिलक ब्रिज) को जरूरत पड़ने पर शाहदरा-साहिबाबाद के रास्ते चलाया जाएगा। डिब्रूगढ़ राजधानी और देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस को साहिबाबाद-शाहदरा-पुरानी दिल्ली-नई दिल्ली के रास्ते चलाया जाएगा। सियालदाह-नई दिल्ली राजधानी, सियालदाह-बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस और रांची-नई दिल्ली राजधानी को भी जरूरत पड़ने पर साहिबाबाद-शाहदरा-पुरानी दिल्ली-नई दिल्ली के रास्ते चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को रोक कर भी चलाया जाएगा। इनमें सिरसा-तिलक ब्रिज एक्सप्रेस, नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी, जम्मूतवी-पुणे झेलम एक्सप्रेस, नई दिल्ली-बनारस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल, मुंबई सेंट्रल-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस, कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली शताब्दी, बनारस-नई दिल्ली एक्सप्रेस और इस्लामपुर-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस शामिल हैं।

इनसाइड

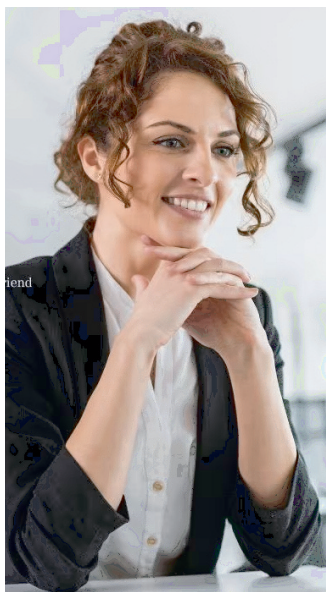

होम ऑफिस के दौरान ऑनलाइन मीटिंग के लिए इस तरह करें कैमरा फ्रेंडली मेकअप, दिखेंगी प्रोफेशनल

ऑनलाइन मीटिंग के दौरान कैमरा फ्रेंडली मेकअप के लिए लिपस्टिक जरूरी है. Image- Canvaऑनलाइन मीटिंग के दौरान कैमरा फ्रेंडली मेकअप के लिए लिपस्टिक जरूरी है. Image- Canva ऑनलाइन मीटिंग के दौरान अगर आप बॉस या क्लाइंट्स के सामने प्रोफेशनल लुक कैरी करना चाहती हैं तो यहां कुछ कैमरा फ्रेंडली मेकअप टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकती हैं. कैमरा फ्रेंडली मेकअप करते समय फाउंडेशन का इस्तेमाल जरूर करें. आपके पास कम समय है तो कैमरे के सामने आने से पहले चेहरे को कंसीलर की मदद से स्पॉटलेस बना सकती हैं. Camera Friendly Makeup Tips : आज भी कई लोगों का काम घर से चल रहा है यानि वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) हो रहा है. वर्क फ्रॉम होम करते समय कई बार बॉस, कलीग्स या क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ती है. हमें कैमरे के सामने लाइव मीटिंग का भी हिस्सा बनना पड़ता है. अब ऐसे में कैमरा पर अच्छा और प्रोफेशनल दिखना काफी जरूरी है. कई लोगों की ये आदत होती है कि वे घर पर रहते रहते कैजुअल हो जाते हैं और एकाएक मीटिंग शेड्यूल होने पर कैजुअल लुक में ही कैमरे के सामने आ जाते हैं. ऐसे में अगर आप महिला हैं और दफ्तर या क्लाइंट्स के सामने प्रोफेशनल लुक कैरी करना चाहती हैं तो यहां कुछ कैमरा फ्रेंडली (Camera Friendly) मेकअप टिप्स (Makeup Tips) बताए जा रहे हैं, जिन्हें फॉलोकर आप मिनटों में मीटिंग के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे.

1.मैट फिनिश मेकअप करें

मैट फिनिश मेकअप प्रोडक्ट आपको कैमरा फ्रेंडली लुक देता है. अगर आप ग्लॉसी प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगी तो हो सकता है कि कैमरे के दूसरे तरफ आपका मेकअप बहुत ही ब्राइट या चमकीला लगे. ऐसे में फॉर्मल मीटिंग के दौरान आप ऑड फील कर सकती हैं. इसलिए जूम मीटिंग के लिए अगर आप तैयार हो रही हैं तो ग्लॉसी मेकअप से दूर रहें.

2.कंसीलर का करें प्रयोग

अगर आपके पास बहुत ही कम समय है तो आप कैमरे के सामने आने से पहले चेहरे को कंसीलर की मदद से स्पॉटलेस बना सकती हैं. आप उन पॉइंट्स पर कंसीलर अप्लाई करें जो कैमरे पर डार्क नजर आते हैं. इसके लिए आप अपनी रिंग फिंगर की मदद से चेहरे के स्पॉट या डार्क सर्कल एरिया पर कंसीलर अप्लाई करें.

3.कंप्लीट लुक के लिए करें फाउंडेशन का प्रयोग

कैमरा फ्रेंडली मेकअप करते समय फाउंडेशन का इस्तेमाल जरूर करें. जब आप कंसीलर के बाद फाउंडेशन अप्लाई करती हैं तो स्किन एक समान नजर आता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि मेकअप नो मेकअल लुक में हो. शादी या पार्टी मेकअप ना लगे.

4.हल्का आई मेकअप भी जरूरी

कैमरे के सामने आपकी आंखें फ्रेश लगना जरूरी है. इसके लिए आप आईलाइनर या काजल का प्रयोग कर सकती हैं. अगर इनका प्रयोग नहीं करना चाह रही हैं तो आप मस्कारा से भी काम चला सकती हैं. इससे आपकी आंखें बुझी बुझी नहीं दिखेंगी और ज्यादा फ्रेश नजर आएंगी.

5.करें लाइट शेड लिपस्टिक का प्रयोग

कैमरा फ्रेंडली मेकअप के लिए लिपस्टिक जरूरी है. इसके लिए आप किसी डार्क शेड की लिपस्टिक की बजाए सोबर कलर का प्रयोग करें. आप पीच या लाइट पिंक कलर शेड का प्रयोग कर सकती हैं. इससे आप ऑफिस मीटिंग में जितना सोबर दिखेंगी उतनी ही प्रोफेशनल भी लगेंगी.

आधी आबादी को मिला सम्मान, गणतंत्र दिवस पर पहली बार BSF की महिला शक्ति करेगी प्रदर्शन

बीएसएफ ऊंट टुकडी के साथ इस बार महिला शक्ति भी कदम ताल मिलाएगी. बीएसएफ की महिला टुकड़ी के ऊंट पर सवार होने के लिए प्रसिद्ध डिजाइनर राघवेंद्र राठौर ने पोशाक डिजाइन की है.

इस बार गणतंत्र दिवस 2023 में आधी आबादी यानी नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए परेड में इस बार खास व्यवस्था की गई है. इस बार गणतंत्र दिवस की परेड 2023 में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करती आईं. ये महिला कैमल राइडर्स बीएसएफ ऊंट टुकड़ी के कदम से कदम मिलाएंगी. यह पहला मौका है जब बीएसएफ ऊंट टुकड़ी के हिस्से के रूप में बीएसएफ की महिला गार्ड ऊंट सवार गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी.

6 इलेक्ट्रोलाइट फूड जो महिलाओं को अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए शामिल

शरीर में पानी की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर को कई तरह ही बीमारियों का सामना करना पड़ता है. इलेक्ट्रोलाइट नामक पोषक तत्व की कमी ज्यादातर बच्चों और औरतों में देखने को मिलती है. बच्चों में उल्टी, दस्त या डायरिया की वजह से ये परेशानी होती है, जबकि औरतें अपनी दिनचर्या में आलस के चलते कम पानी पीने की वजह से इसकी कमी की शिकार हो जाती हैं. ऐसे में महिलाओं को खासकर अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए पहले जानते हैं कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी क्यों होती है ?

क्या है कारण

स्विडिश डॉटओआरजी के मुताबिक, इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कई कारण हैं, जिसमें उल्टी-दस्त होना, भरपूर मात्रा में पानी या तरल पदार्थ का सेवन न करना आदि शामिल हैं.

इलेक्ट्रोलाइट की कमी से क्या होता है ?

अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए तो थकान, सुस्ती के साथ-साथ, उल्टी, दस्त की परेशानी होती है. इससे शरीर में पानी की और ज्यादा कमी होने लगती है. इलेक्ट्रोलाइट की कमी के चलते दिल की धड़कन भी सुस्त पड़ने लगती है, जो बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है. इसके अलावा, सारे दिन थकान, सुस्ती और आलस शरीर में रहता है. डाइट में कुछ खास फूड शामिल करके महिलाएं अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को परफेक्ट कर सकती हैं.

नारियल पानी

हेल्दीफाईमी डॉट कॉम के अनुसार, नारियल इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. ये एक प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है और नारियल पानी में पोटैशियम, मैंगनीज, विटामिन सी, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, इसलिए नारियल पानी का नियमित सेवन करना चाहिए.

संतरा

सर्दियों में महिलाओं को संतरे का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी की जा सके. संतरे में मौजूद विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, एमिनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, मिनरल्स और फाइबर जैसे पोषक तत्व ना केवल बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन अच्छा करेंगे बल्कि इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएंगे.

छाछ

छाछ यानी मट्ठा में भी इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाने की क्षमता होती है. इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च को मिलाकर पीने से इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाएगी.

केला

केले में भरपूर इलेक्ट्रोलाइट युक्त मिनिरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करके इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन दूर करते हैं. इसमें भरपूर फाइबर होता है. केले में पोटैशियम, मैंगनीज, विटामिन बी 6, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को दूर किया जा सकता है और शरीर को जरूरी पावर भी मिलती है.

सर्दियों में हरी सब्जियों खासकर पालक का खूब सेवन करना चाहिए. पालक में इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपूर मात्रा होती है और इसके सेवन से शरीर को सभी तरह के जरूरी मिनिरल्स, विटामिन, फाइबर और कैल्शियम मिलते हैं. इसके सेवन से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन होता है और प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है.

इनके अलावा, अनार, स्ट्रॉबेरी, आलूबुखारा जैसे फल खाने से भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ता है. सब्जियों की बात करें तो आलू खाने से भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा बढ़ती है और शरीर को ऊर्जा के साथ-साथ स्फूर्ति मिलती है.

मिसकैरेज से जूझ रही महिला के लिए फैमिली सपोर्ट जरूरी, हो सकती है सदमे की शिकार, ऐसे रखें ख्याल

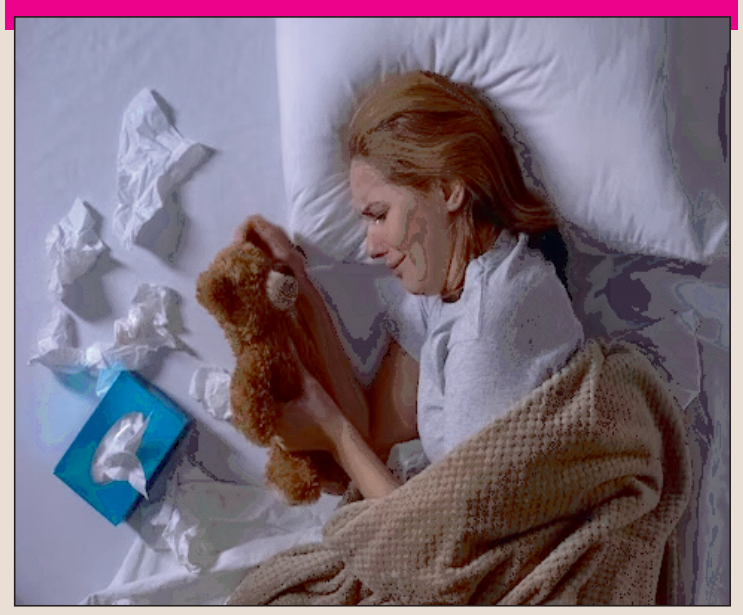

किसी भी महिला के लिए मां बनना दुनिया के सबसे सुखद अनुभवों में से एक होता है. लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की समस्या से मिसकैरेज हो जाना महिला के जीवन के सबसे कठिन दौर में से एक होता है. इस समय अगर परिवार का साथ ना मिले तो महिला शारीरिक रूप से तो कमजोर होती ही है, मानसिक रूप से भी कई खतरनाक बीमारियों की गिरफ्त में जा सकती है.

प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज या गर्भपात हो जाना ना केवल महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह गहरे आघात का सामना करती है. कई बार ये भावनात्मक चोट इतना गहरा होता है कि वह खुद को तनाव और अवसाद से बाहर नहीं निकाल पाती. ऐसे हालात में घर का माहौल और पार्टनर का साथ सकारात्मक होना बहुत जरूरी है. मिसकैरेज के बाद महिलाएं कई तरह के नकारात्मक भावनाओं से जूझती रहती हैं और इसका असर उनके शरीर और स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगता है. ऐसे में अगर पार्टनर और परिवार का इमोशनल सपोर्ट ना मिले तो वो और भी सदमें में जा सकती है. द हेल्थशॉटके मुताबिक, एक स्टडी में पाया गया है कि मिसकैरेज के बाद महिलाएं पोस्टट्रॉमेटिक स्ट्रेस, डिप्रशन और एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं और इससे उबरने में उन्हें 9 महीने तक का समय लग सकता है. ऐसे में जरूरी है कि परिवार वाले महिला का केयर करें और सही तरह से देखभाल करना जानें. यहां हम बता रहे हैं कि मिसकैरेज के बाद किस तरह महिला का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकता है.

मिसकैरेज से जूझ रही महिला का इस तरह रखें ख्याल

सेहत का रखें ख्याल

मिसकैरेज के बाद रिकवरी के लिए जरूरी है कि महिला अपने हाइड्रेशन, खान पान, वर्कआउट, नींद आदि का पूरा ख्याल रखे. लेकिन अगर महिला ऐसा नहीं कर पा रही तो आप उसकी मदद करें और अपनेपन से सेल्फ केयर के लिए भी मोटिवेट करें.

पार्टनर करे सपोर्ट

कई पार्टनर ये सोचते हैं कि इस बात पर चर्चा करने से वे उसे और भी दुख पहुंचाएंगे. लेकिन कई बार सही संवाद ना होने की वजह से समस्या और भी बढ़ जाती है. इसलिए आप बिना चोट पहुंचाएं महिला के साथ संतुलित व्यवहार करें और उससे बातचीत जारी रखें.

समय दें

परिवारवालों के लिए भी ये मुश्किल भरा समय होता है लेकिन उन्हें यह समझना जरूरी है कि मिसकैरेज के बाद भावनात्मक रूप से ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है. इसलिए जल्दबाजी ना करें.

बेटियों को रियायती दरों पर पढ़ाएगा सीएसजेएम विश्वविद्यालय, जानें क्या है योजना

कानपुर स्थिति छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में कम फीस पर कमजोर वर्ग के बेटियों का दाखिला किया जाएगा. यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन की बैठक में लिया गया.

नई दिल्ली। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हुए आज कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने बेटियों को रियायती दरों पर पढ़ाने की योजना शुरू की. इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि बेटियों की शिक्षा को और मजबूत करने के लिए यह फैसला बोर्ड बैठक में लिया गया. उन्होंने बताया कि अब परिवार में एक या दो बेटियां होने पर विश्वविद्यालय में प्रवेश फीस और स्कॉलरशिप में मदद दी जाएगी. सीएसजेएमयू ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को सार्थक करने के लिए कदम बढ़ाया है.

वहीं विवि कुलपति ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अगले सत्र से इसकी शुरुआत की जाए ताकि जल्द से जल्द लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके. कुलपति के अनुसार कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं. ऐसे में यह योजना ऐसे वर्ग के लिए वरदान साबित होगी.

आज की बड़ी खबरें

विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि बेटियों के बारे में ऐसी योजना लाने वाला छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा. उन्होंने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन की यह मंशा है कि हर वर्ग की बेटी को इस योजना का लाभ मिल सके. इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जानकारी दी जाएगी, इसके अलावा प्रवेश में वरीयता के साथ-साथ आर्थिक मदद भी की जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए तरह-तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं विश्वविद्यालय की इस योजना का लाभ ग्रामीण इलाके के कमजोर वर्ग की बेटियों को ज्यादा होगा. शर्मा ने कहा कि विवि के कॉलेजों में भी नए सत्र से बेटियों की शिक्षा के संबंध में कई निर्णय लिए जाएंगे और बेटियों की शिक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव भी किए जाएंगे.

इनसाइड

यूजी, पीजी के तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर लग सकती है मुहर, अकादमिक काउंसिल की बैठक आज

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को अकादमिक परिषद की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूजी-पीजी के तीसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम और पीजी के दाखिले के लिए दाखिला पात्रता को मंजूरी दिए जाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की ओर से शुरू होने वाले बीए ऑनर्स मनोविज्ञान व उसके लिए तय की गई फीस को पास कराने के लिए बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा डीयू के सभी छात्रों के लिए शुरू किए गए कुछ अन्य कौशल आधारित कोर्सेज पर भी मुहर लगेगी। मालूम हो कि अभी तक अकादमिक परिषद से पहले व दूसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को ही मंजूरी मिली है। दरअसल शिक्षक संगठन अलग-अलग सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को पास कराने पर विरोध जताते आ रहे हैं। संगठनों का कहना है कि छात्रों को एक बार में ही यह पता होना चाहिए कि उन्हें अगले सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना है। डीयू में इस बार (2023-24) स्नातकोत्तर (पीजी) के दाखिले यूजी (स्नातक) की तरह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट (सीयूईटी) होने हैं। ऐसे में स्नाकोत्तर स्तर की दाखिला पात्रता पर बैठक में विचार किया जाएगा। 2023-24 के तहत दाखिले के लिए यूजी कोर्सेज की प्रोग्राम आधारित पात्रता में कोई बदलाव नहीं होगा। वह बीते साल की तरह ही होंगे।

स्नातकोतर कोर्सेज के दाखिले सीयूईटी स्कोर से होंगे। डीयू के पीजी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को सीयूईटी परीक्षा को देना अनिवार्य है। प्रोग्राम आधारित पात्रता के तहत दो श्रेणी होंगी। पहली श्रेणी में किसी अन्य विवि से स्नातक या स्नातकोत्तर करने वाले छात्र होंगे, जबकि दूसरी श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय से ऑनर्स या बैचलर डिग्री करने वाले छात्र होंगे। दोनों ही श्रेणी में पचास-पचास फीसदी सीटें होंगी। डीयू के नॉन कॉलिजिऐट वूमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) के पीजी प्रोग्राम में भी दाखिले सीयूईटी स्कोर से ही किए जाएंगे। जबकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पीजी प्रोग्राम में दाखिले दूरस्थ शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर मेरिट पर होंगे।

आईपी यूनिवर्सिटी के पीजी (आयुर्वेद) प्रोग्राम में सीट आवंटन आज

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आईपी यूनिवर्सिटी) ने सत्र 2022-23 के लिए पीजी (आयुर्वेद) प्रोग्राम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की है। आज से सीटों का आवंटन ऑफलाइन शुरू होगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 18 सीटें उपलब्ध हैं। चार सीट रचना शरीर, चार सीट काया चिकित्सा, तीन सीट रोग निदान और विकृति विज्ञान, तीन सीट पंचकर्मा और चार सीट क्रिया शरीर में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम दिल्ली के चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में उपलब्ध है।

एआईएपीजीईटी 2022 की प्रवेश परीक्षा के ऐसे सफल उम्मीदवार, जिन्होंने बीएएमएस की डिग्री आईपी यूनिवर्सिटी के किसी संबद्ध कालेज से प्राप्त की है और जिन्होंने इस प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन किया था, उनके लिए सीटों का आवंटन द्वारका कैंपस में ऑफलाइन किया जाएगा। अन्य जानकारियां यूनिवर्सिटी की दोनों websites https://ipu.admissions.nic.in और https://ipu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

नए निगम पार्षदों ने भोजपुरी, संस्कृत और हरियाणवी में भी ली शपथ, राफिया से शुरू हुआ अंग्रेजी का सिलसिला

नई दिल्ली। कई महिला पार्षदों ने फर्राटे से अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। खास बात है कि अंग्रेजी में शपथ लेने वाली पार्षदों में मुस्लिम महिला पहली थी। इसके बाद कई महिलाओं ने अंग्रेजी में शपथ ली। वार्ड नंबर-78 बाजार सीताराम से आप पार्षद राफिया माहिर ने अंग्रेजी में शपथ लेने की शुरुआत की। एमसीडी सदन की बैठक में मंगलवार को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा भोजपुरी, संस्कृत व हरियाणवी में भी कुछ पार्षदों ने शपथ ली। कई महिला पार्षदों ने फर्राटे से अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की। खास बात है कि अंग्रेजी में शपथ लेने वाली पार्षदों में मुस्लिम महिला पहली थी। इसके बाद कई महिलाओं ने अंग्रेजी में शपथ ली।

26 जनवरी की सौगात: आंखों की मुफ्त जांच कराएगी केजरीवाल सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराया

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ढेरों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। आजादी दिलाकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आजादी को और संभालने की, सुरक्षित रखने और इसे और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

दिल्ली में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने दिल्लीवालों के लिए बड़ी सौगात का एलान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उपराज्यपाल व भाजपा पर हमला बोला।

केजरीवाल ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए भारत माता के जयकारे लगवाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो दूसरी तरफ 75वां स्वतंत्रता दिवस।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे ढेरों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। आजादी दिलाकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आजादी को और संभालने की, सुरक्षित रखने और इसे और सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

चीन को लेकर बोला केंद्र पर हमला

आज के दिन दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आजकल हम मीडिया में पढ़ते हैं कि चीन पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश पर आंख लगाए बैठा है और हमारी जमीन कब्जा ली है। अपनी पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक चीन से लड़ते हैं तो दूसरी तरफ भारत की सभी सरकारों का फर्ज बनता है कि हम उनका उत्साहवर्धन करें।

एक तरफ चीन हमें आंखें दिखा रहा है और दूसरी तरफ हम उससे अपना व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। हम चीन को अमीर बनाते जा रहे हैं। हमारे पैसे से वो और हथियार खरीद कर सैनिक बैठाकर हमसे युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है।

केजरीवाल ने पूछा, हम जो सामान उनसे खरीदते हैं वो अपने देश में भी बन सकता है। यदि हमारे देश में ये सब बनेगा तो हमारे देश में नौकरी भी मिलेगी और चीन को भी संदेश जाएगा कि हम खुद अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हम अपने देश के व्यापारियों को इतना दुखी कर रहे हैं कि वो देश छोड़कर जा रहे हैं और हम चीन से सामान खरीद रहे हैं।

इसके बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों का उदाहरण देकर भी केंद्र सरकार पर राज्यपाल के माध्यम से अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया।

दिल्लीवालों को सौगात की घोषणा की

केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस का भाषण देते हुए दिल्लीवालों के लिए एक बड़ी सौगात का एलान किया। उन्होंने कहा कि अब से सरकार दिल्लीवालों की आंखों की मुफ्त जांच करवाएगी। वह बोले, जरूरत पड़ने पर फ्री चश्मा और ऑपरेशन भी करवाएगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह बात तेलंगाना सरकार से सीखी है।

अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में महंगाई सबसे कम, उपराज्यपाल और केन्द्र पर साधा निशाना

दिल्ली। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हम उससे व्यापार बढ़ाते ही जा रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने चीन से 65 बिलियन डॉलर, तो 2021 में 95 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। स्टार्ट-अप, ईवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीसीटीवी और हरित क्षेत्र में दिल्ली देश में नंबर बन चुकी है। यह बात केंद्र सरकार रिपार्ट में सामने आई है। इतना ही नहीं राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसों का सफर और तीर्थ यात्रा मुफ्त होने की वजह से पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। यह बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कहीं। इससे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत वंदेमातरम गीत के साथ हुई। परेड कमांडर एसीपीपी अभिनंदन के अनुरोध पर निरीक्षण जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने तीन टुकड़ियों में विभाजित दिल्ली पुलिस का दल, होमगार्ड, अग्निशमन सेवा, एनसीसी कैडेट्स का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस का पाइप बैंड, होमगार्ड, एनसीसी, सरकारी स्कूलों के बच्चे के परेड दल ने भी मुख्यमंत्री को सलामी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को खाने-पीने की वस्तुओं से जीएसटी हटाकर लोगों को महंगाई से राहत देने के साथ ही जीएसटी को सरल करना चाहिए।

चीन के बहाने केंद्र पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और हम उससे व्यापार बढ़ाते ही जा रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने चीन से 65 बिलियन डॉलर, तो 2021 में 95 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। हमारा फर्ज बनता है कि हम बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रहे अपने सैनिकों का साथ दें और चीन का बहिष्कार कर उनको कड़ा संदेश दें। चीन ने हमारे देश की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह सभी भारतवासियों के लिए चिंता का विषय है। हमारे सैनिक चीन के सैनिकों से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पूरी बहादुरी के साथ हमारे सैनिक बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ, हमारे सैनिक बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की सारी सरकारों और हर भारतवासी का भी फर्ज बनता है कि हम उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें।

उपराज्यपाल पर सीएम ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाकर देश में जनतंत्र की स्थापना की, जहां जनता और चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो से जनतंत्र पर आंच आने लगी है। दिल्ली एक राज्य ऐसा है, जहां की चुनी हुई सरकार ने ढेरों कानून पास किए, पर उपराज्यपाल उस पर दस्तखत करने को तैयार नहीं हैं। एक व्यक्ति विशेष में जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। ये जुडिशरी, राज्य सरकारों, किसानों, छात्रों और व्यापारियों से लड़ रहे हैं। अगर हम लड़ाई-झगड़ा छोड़ मिलकर काम करें, तो भारत को दुनिया का नंबर-1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।

पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में महंगाई की दर 3 फीसद है, जबकि गुजरात में 7 फीसद, हरियाणा में 7.8 फीसद है, जो दिल्ली से ढाई गुना ज्यादा है। मध्यप्रदेश में महंगाई की दर 7.5 फीसद है। मध्यप्रदेश में भी दिल्ली से ढाई गुना ज्यादा महंगाई है। अगर कोई सामान दिल्ली में 100 रुपए की मिलती है, तो हरियाणा और मध्यप्रदेश में 250 रुपए में बिकती है। उत्तर प्रदेश में महंगाई दर 6.8 फीसद है। पूरे देश में सबसे सस्ती चीजें और सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, क्योंकि आज दिल्ली में बिजली, पानी मुफ्त है।

देश की सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है

मुख्यमंत्री ने अपने तेलंगाना दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की सरकार चार करोड़ लोगों की आंखों का टेस्ट करवा रही है। मुफ्त चश्मा देगी। यह देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सभी को एक-दूसरे से सीखने की जरूरत है। आज तेलंगाना यह काम किया। हम सीख कर आए और दिल्ली में करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने भी वहीं पर ऐलान किया कि पंजाब में भी लागू करेंगे।

मौसम ने ली करवट, कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, जानें गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जनवरी शाम को व 29 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 19.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 10.6 डिग्री दर्ज किया गया।

दिल्ली में मौसम ने करवट ले ली है। बुधवार को मौसम पूरी तरह से बदल गया। सुबह से आसमान में हल्के बादल थे जो दोपहर बाद पूरी तरह से छा गए। देर शाम कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस कारण अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक दर्ज किया गया। दोपहर में चली तेज हवाओं ने ठंडक का अहसास कराया।

दिल्ली में मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण नवंबर व दिसंबर में बारिश नहीं हुई है। वहीं जनवरी में भी बारिश ना के बराबर ही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जनवरी शाम को व 29 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है। बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 19.3 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम में बदलाव के कारण गुरुवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने की संभावना है।

27 व 28 को न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इस कारण से एक बार फिर से ठिठुरन का अहसास होगा। इस दौरान तापमान 06 डिग्री तक रहने का अनुमान है। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। गुरुवार को सुबह के समय हल्के कोहरे की भी संभावना है। दिल्ली के जाफरपुर इलाके में सबसे कम 16.6 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान दर्ज हुआ।

जबकि रिज इलाके में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुरूग्राम में अधिकतम तापमान 17.0 और न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 18.8 और न्यूनतम तापमान 13.3 और नोएडा में अधिकतम तापमान 19.2 और न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

पूर्वानुमानः आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्का कोहरे की संभावना।

अधिकतम तापमानः 19.3 डिग्री सेल्सियस

न्यूनतम तापमानः 10.6 डिग्री सेल्सियस

26 जनवरी को सूर्यास्तः शाम 5:55 मिनट

दिल्ली पुलिस को मिली तीन शिकायतें, एबीवीपी ने किया ये बड़ा दावा

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जेएनयू में पत्थरबाजी हुई होती तो किसी को चोट लगती। इस मामले में किसी की एमएलसी नहीं बनी है। दिल्ली पुलिस जेएनयू के बाहर तैनात हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हुए विवाद में दिल्ली पुलिस को तीन शिकायतें मिली हैं। इनमें से दो शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दी हैं और एक शिकायत आईसी घोष ने दी है। इस मामले में आईसा के एक छात्र की एमएलसी बनी है, जो कि पुलिस को मिल गई है। एमएलसी में छात्र को कोई अंदरूनी चोट नहीं लगने की बात कही गई है।

पुलिस ने शिकायतें ले ली हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। आईसी घोष ने कहा है कि अभी उसने प्रारंभिक शिकायत दी है वह विस्तार से लिखित शिकायत बुधवार दोपहर बाद देगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जेएनयू में पत्थरबाजी हुई होती तो किसी को चोट लगती। इस मामले में किसी की एमएलसी नहीं बनी है। दिल्ली पुलिस जेएनयू के बाहर तैनात हैं और स्थिति को नियंत्रण में रखा हुआ है।

एबीवीपी का ये है दावा

जवाहर लाल नेहरू कैंपस में बीती रात हुए विवाद को लेकर एबीवीपी के एक छात्र गौरव ने दावा किया है कि वह अपने कई साथियों के साथ चाय पीने गया था तब लेफ्ट के छात्रों ने उन्हें जबरदस्ती पड़क लिया। छात्र गौरव दिल का मरीज है और हाथपाई से उसकी तबियत खराब हो गई थी।

सगाई समारोह में पत्नी ने की हर्ष फायरिंग, सिपाही पति को लगी गोली

बुलंदशहर। परिजनों ने घायल युवक को हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां वह आईसीयू में है, हालांकि, वर्तमान में वह खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है घायल युवक मुजफ्फरनगर मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग में तैनात है। शादी, सगाई व अन्य समारोह में रोक के बावजूद हर्ष फायरिंग थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं, अब नगर के मोहल्ला रामनगर में मंगलवार शाम को सगाई समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हो गई। इस दौरान एक महिला ने हर्ष फायरिंग कर दी, लेकिन गोली उसके पति के बाजु में जा लगी। घायल पति उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। उसे हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुलावठी पुलिस ने घटना से अनभिज्ञता जताई है।

नगर के मोहल्ला रामनगर में एक युवक का मंगलवार को सगाई समारोह था। सगाई समारोह में युवक का चचेरा भाई और चचेरे भाई की पत्नी भी सम्मिलित होने के लिए आई थीं। सगाई के दौरान कुछ रिश्तेदारों ने हर्ष फायरिंग करनी शुरू कर दी। जिस युवक की सगाई थी उसके चचेरे भाई ने अपनी पत्नी से हर्ष फायरिंग करने को कहा और हथियार पत्नी को दे दिया। पत्नी ने हर्ष फायरिंग की तो गोली उसके पति के ही बाजु में जा लगी।

परिजनों ने घायल युवक को हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां वह आईसीयू में है, हालांकि, वर्तमान में वह खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है घायल युवक मुजफ्फरनगर मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग में तैनात है। उसकी कुछ माह पूर्व ही शादी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। न ही कोई तहरीर मिली है। यदि ऐसा है तो जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद बना उद्यमियों की पसंद

3200 उद्यमी करेंगे 92000 करोड़ रुपये का निवेश

एनटीवी न्यूज

गाजियाबाद। इन्वेस्टर सम्मिट में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि गाजियाबाद का माहौल उद्योगों को लगाने के लिए अनुकूल बना है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से जेवर हवाई अड्डा बहुत नजदीक है, इससे माल ढुलाई में फायदा मिलेगा। देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल और बेहतर रेल नेटवर्क गाजियाबाद में मौजूद है।

गाजियाबाद उद्यमियों की सबसे बड़ी पसंद बन गया है। यूपी में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट से पहले जिला स्तर पर हुई गाजियाबाद इन्वेस्टर्स समिट में से 3200 से ज्यादा उद्यमियों ने 92,000 करोड़ रूपए निवेश करने का निर्णय लिया है। उद्यमियों ने विभिन्न विभागों के माध्यम से जिला प्रशासन को प्रस्ताव सौंप दिए हैं। इनमें से 2620 उद्यमियों ने करीब 72,000 करोड़ रुपये के एम ओ यू भी साइन कर लिए हैं।

बुधवार को कौशांबी के होटल रेडिसन ब्लू में हुई समिट में जीडीए जिला उद्योग केंद्र नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आवास विकास परिषद समेत कई विभागों ने निवेशकों के सामने यूपी सरकार की ओर से उद्यमियों को मिलने वाली छूट व अन्य पॉलिसी की जानकारियों का प्रेजेंटेशन किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद में नेशनल हाईवे नौ से लेकर राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मंडोला तक नई रोड बनाई जाएगी। इस मार्ग को मंडोला में दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह मार्ग गाजियाबाद के उद्योगों के लिए संजीवनी साबित होगा। उन्हें माल ढुलाई के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। समिट में उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उद्यमियों को पहली बार कैपिटल में भी चार करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा उनके लिए सस्ती दरों पर जमीन दिलाने और प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर स्टांप शुल्क में छूट भी दी जाएगी। औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण पर भी यूपी सरकार का फोकस बड़ा है। मंत्री राकेश सचान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को अधिकतम 10 करोड़ तक का अनुदान दिया जाएगा।

इन्वेस्टर सम्मिट में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि गाजियाबाद का माहौल उद्योगों को लगाने के लिए अनुकूल बना है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से जेवर हवाई अड्डा बहुत नजदीक है, इससे माल ढुलाई में फायदा मिलेगा। देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल और बेहतर रेल नेटवर्क गाजियाबाद में मौजूद है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद को कानपुर फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से अपील की है कि सरकार ने जो योजनाएं उनके लिए संचालित की हैं और जो छूट दी है। उसका उपयोग कर गाजियाबाद में ज्यादा से ज्यादा निवेश करें ताकि बेहतर लाभ कमाया जा सके। इन्वेस्टर सम्मिट में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, मेयर आशा शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, विधायक अतुल गर्ग नंदकिशोर गुर्जर सुनील शर्मा अजीत पाल त्यागी और मंजू शिवाज समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे।

तेज रफ्तार कार ने मीडियाकर्मी को मारी टक्कर, कार के नीचे आया उनका कुत्ता, मौत

गाजियाबाद। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने के पीछे लाजपत नगर में बुधवार सुबह घर के बाहर कुत्ता घुमा रहे मीडियाकर्मी निर्दोष तोमर को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस बीच गाड़ी के नीचे दबने से उत्तराखंड के भूटिया नस्ल के कुत्ते की मौत हो गई। मीडियाकर्मी ने बताया कि वह साढ़े 3 महीने पहले उत्तराखंड के केदारनाथ से 40,000 रुपये में यह कुत्ता खरीद कर लाए थे। मौके पर गुस्साए लोगों ने आरोपी गाड़ी चालक को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में मीडियाकर्मी की तरफ से आरोपी चालक के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। एसीपी पूनम मिश्रा का कहना है कि मृत कुत्ते को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जबकि चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रहे हैं।

40 मिनट में गाजियाबाद से पहुंचेंगे फरीदाबाद

एनटीवी संवाददाता

गाजियाबाद। फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद (एफएनजी) शुरू होने के बाद गाजियाबाद से फरीदाबाद पहुंचने में चालीस मिनट का समय लगेगा। अभी एक से डेढ़ घंटा घर पहुंचने में लगता है। एफएनजी के देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद गाजियाबाद से देहरादून पहुंचने में दो से ढाई घंटे लगेगा, जबकि अभी चार से पांच घंटे लगते हैं। इससे शहर के अन्य हिस्सों में जाना भी आसान हो जाएगा और जाम से जूझना नहीं पड़ेगा।

छिजारसी के पास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए सिद्धार्थ विहार से होकर हिंडन नदी को पार कर हिंडन मेट्रो रीवर से होकर इंटरनेशनल स्टेडियम के पास मंडोला में जुड़ेगा। इस मार्ग की लंबाई लगभग 25 किमी होगी। इसका प्रस्तुतीकरण आज कौशांबी में आयोजित इंवेस्टर समिट में होगा।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने के बाद हिंडन नदी पर पुल बनाकर पार होगा। साईं उपवन, हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन के पास से होते हुए राजनगर एक्सटेंशन को जाने वाली सड़क में जुड़ेगा। वहां से करहेड़ा रोटरी को पार कर सिटी फॉरेस्ट से आगे दूसरी बार हिंडन नदी पुल बनाकर भनेड़ा खुर्द के पास नार्दन पेरिफेरल रोड से जुड़ेगा। यहां टीला मोड़, निस्तौली और लोनी की तरफ जाने वाले लोग नार्दन पेरिफेरल पर चढ़कर गंतव्य तक जा सकेंगे। जिन लोगों को देहरादून की तरफ जाना होगा। वह इस मार्ग पर नार्दन पेरिफेरल रोड को पार कर सीधे मंडोला के पास दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़कर देहरादून जा सकेंगे। एफएनजी बनने के बाद प्रतिदिन लाखों लोगों को आवागमन में समय की बचत होगी।

एनएचएआई बना सकता है एफएनजी

जीडीए के अधिकारियों ने बताया कि एफएनजी को बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाया जा सकता है। पहले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कवायद की जा रही है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। एफएनजी का नोएडा में 20 किमी और गाजियाबाद में 25 किमी हिस्सा पड़ रहा है। गाजियाबाद में कुछ क्षेत्र जैसे सिद्धार्थ विहार से राजनगर एक्सटेंशन तक एलीवेटिड और कुछ हिस्सों में जमीन पर बनाया जाएगा।

मिल चुकी है हरी झंडी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह का कहना है कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से लोगों को गंतव्य तक आवागमन में सहूलियत मिलेगी। वहीं, दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि एनएचएआई ने सर्वे के बाद छह लेन का मार्ग बनाकर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए हरी झंडी दे दी है।

इनसाइड

तेज रफ्तार कार एनएच-9 से नीचे गिरी, चालक घायल

गाजियाबाद। क्रासिंग रिपब्लिक क्षेत्र के बहरामपुर के पास एनएच-9 पर सोमवार शाम करीब पौने चार बजे तेज रफ्तार इनोवा कार खंभे से टकरा कर रेलिंग तोड़ते हुए फ्लाईओवर से नीचे गिरकर पलट गई। कार में केवल चालक सवार था। एयरबैग खुलने से वह बाल-बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे कार में से निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस झपकी लगने या किसी वाहन को बचाने के कारण हादसा होने का अंदेशा जता रही है। दिल्ली के करावल नगर निवासी सोनू लालकुआं स्थित एक कारोबारी के यहां चालक है। सोमवार शाम वह कार लेकर नोएडा की ओर जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को उठवाकर साइड कराया। पुलिस सोनू से हादसे होने के कारण पता करने का प्रयास कर रही है। एसीपी वेव सिटी रवि प्रकाश सिंह का कहना है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसा होने का कारण पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक कार हाईवे से खंभे से टकराकर रेलिंग तोड़कर नीचे आकर गिरकर पलट गई थी।

गार्डन गैलेरिया मॉल बन रहा मारपीट का अखाड़ा

मॉल में दर्जनों की संख्या में पब व रेस्ट्रो बार हैं। यहां रोजाना एक-दो घटनाएं मारपीट की होती हैं। अब मॉल में दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा के सेक्टर-39 कोतवाली क्षेत्र स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के सूत्रा पब में बृहस्पतिवार रात शराब के नशे में दो पक्षों में विवाद हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीब आठ सेकंड के इस वीडियो में दो पक्षों के बीच मारपीट व धक्का-मुक्की होती दिख रही है। इसका वीडियो एक सोशल मीडिया यूजर ने पुलिस को टैग करते हुए वायरल कर दिया। पुलिस ने संज्ञान लेकर मामले की छानबीन शुरू की है। एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि वीडियो को कई लोगों ने साझा किया है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को सूचना नहीं दी गई है। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। घटना रात एक बजे की बताई जा रही है। पब प्रबंधन से भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी।

सीआईए ने तस्कर दबोचा, 18 किलो गांजा बरामद

तावडू। उपमंडल के अंतर्गत बुराका रेलवे फ्लाईओवर के साथ कच्चे रास्ते से मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक कट्टे में 18 किलो 380 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को काबू करने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान अकरम निवासी शिकारपुर थाना तावडू जिला नूंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गाजियाबाद में बनेंगी तीन यूनिवर्सिटी, निवेश के लिए दिया प्रस्ताव

गाजियाबाद। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए अब छात्र-छात्राओं को दूसरे राज्यों या जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। गाजियाबाद में इसी साल तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित होंगी। इन यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कॉरपोरेट घराने बड़ा निवेश करेंगे। बृहस्पतिवार को कौशांबी के होटल रेडिसन ब्लू में होने वाली इंवेस्टर्स समिट में इन तीनों यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पेश होगा।

राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल के बेटे अंजुल अग्रवाल ने मेरठ रोड पर एचआरआईटी के नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को दिया है। इसके अलावा डासना के पास सुंदरदीप यूनिवर्सिटी खोलने के लिए एक बड़े संस्थान की ओर से जिला प्रशासन को प्रस्ताव दे दिया गया है। वहीं, मोदीनगर में मोदी ग्रुप की ओर से केएन मोदी यूनिवर्सिटी स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन को बताया गया है कि उनके पास यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 50 एकड़ जमीन भी उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने इन तीनों प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें पॉलिसी के तहत विभिन्न सहूलियतें भी दी जाएंगी।

यूनिवर्सिटी खुलने से होंगे फायदे

जिले में तीन यूनिवर्सिटी खुल जाने से कई नए कोर्स गाजियाबाद में शुरू हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहेंगे। बेहतर रैंक पाने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ही नौकरी के लिए कई कंपनियां पहुंचने लगती है। इससे पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद छात्र-छात्राओं को नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। दूरदराज के छात्र-छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। एचआरआईटी एजूकेशन समूह की ओर से गाजियाबाद में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव बुधवार को इंवेस्टर्स समिट में दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है। समूह की ओर से यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 5200 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव एचआरआईटी कॉलेज के वाइस चेयरमैन अंजुल अग्रवाल की ओर से दिया जाएगा। - डॉ. अनिल अग्रवाल, राज्यसभा सांसद व एचआरआईटी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन

तीन यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए प्रस्ताव मिला है। तीनों प्रस्तावों पर इंवेस्टर्स समिट में चर्चा होगी। इनके प्रबंधन की ओर से जमीन की उपलब्धता और फंडिंग आदि की जानकारी दी गई है। सड़क, सुरक्षा व परिवहन के नए संसाधन विकसित होने से गाजियाबाद निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश का करीब 22 फीसदी निवेश गाजियाबाद में मिला है। - राकेश कुमार सिंह, डीएम

सभी विभाग निवेशकों के सामने देंगे प्रजेंटेशन

बृहस्पतिवार को होने वाले इंवेस्टर्स समिट में करीब 90 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। निवेशकों और सरकार के बीच अनुबंध होंगे। इस समिट में जीडीए, जिला उद्योग केंद्र, एनएचएआई, आवास विकास परिषद, यूपीसीडा की ओर से निवेशकों के सामने प्रजेंटेशन दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की पॉलिसी में किए गए बदलाव, उद्योगों के लिए मास्टर प्लान में तय किए गए क्षेत्र, एनएचएआई की ओर से भविष्य में विकसित किए जाने वाले सड़क मार्ग और उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।

कई वेरिएंट्स बंद होने के बाद भी कायम है टाटा की इस कार का जलवा , बनी लोगों की पहली पसंद

एसयूवी हो या हैचबैक हर किसी सेगमेंट में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों द्वारा टाटा की गाड़ियों को काफी पसंद किया जाता है। नेक्सन का टाटा की कुल बिक्री में मार्केट शेयर 30 .10 प्रतिशत का रहा है।

भारतीय बाजार में टाटा का नाम आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रहा है, यू कहे तो इसकी बादशाहत आज तक कायम है। एसयूवी हो या हैचबैक हर किसी सेगमेंट में कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोगों द्वारा टाटा की गाड़ियों को काफी पसंद किया जाता है। वहीं अब कंपनी इलेक्ट्रिक कार में भी धूम मचा रही है। दिसंबर के महीने में कंपनी ने 12053 यूनिट्स की सेल की है। इस सेल में सबसे अधिक टाटा की नेक्सन है। अगर दिसंबर 2021 के सेल पर नजर डाली जाए तो कंपनी ने 6.56 प्रतिशत की ग्रोथ की है। वहीं नेक्सन का टाटा की कुल बिक्री में मार्केट शेयर 30.10 प्रतिशत का रहा है।

नेक्सन बनी लोगों की पसंद

अगर नवंबर और अक्टूबर की बात करें तो नेक्सन की सेल टॉप पर रही है। पिछले साल अक्टूबर 2022 में कंपनी ने नेक्सॉन की 13767 यूनिट्स सेल की थी। वहीं नवंबर में इसकी 15871 यूनिट्स की सेल की थी। हालाकिं कंपनी ने साल के आखिरी में कई ऑफर भी पेश किए थे। जिसके कारण दिसंबर में जमकर ब्रिकी हुई थी। वहीं एसयूवी सेगमेंट की बात करें तो कंपनी की अन्य कारों के मुकाबले नेक्सन की ब्रिकी सबसे अधिक रही है।

नेक्सन के बंद हो चुके हैं 6 वेरिएंट

भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। वहीं नेक्सॉन की सेल का ये हाल तब है जब टाटा कंपनी ने इसके 6 वेरिएंट बंद कर दिए हैं। आपको बता दे वाहन निर्माता कंपनी ने नेक्सॉन का एक्स जेड, एक्सजेडए, एक्सजेड प्लस ओ, एक्स जेड प्लस ओ, एक्स जेड प्लस ओ डार्क और एक्सजेड प्लस ओ डार्क वेरिएंट को बंद कर दिया है।

नेक्सॉन फिलहाल कुछ 67 वेरिएंट्स में आती है। इसमें 19 पेट्रोल, 18 डीजल के साथ ही कुछ इलेक्ट्रिक और ऑटोमैटिक वेरिएंट शामिल है। इसकी एक्स शोरूम कीमत कीमत 7.70 लाख रुपये से शुरू होती है।

इनसाइड

देर रात घर लौटने का प्लान? कैब का इस्तेमाल करते समय सेफ्टी के लिए जरूर करें ये काम

आपको सबसे गाड़ी के नंबर की तस्वीर और अपने गाड़ी का लाइव ट्रिप शेयरिंग को अपने किसी करीबी को अपडेट करते रहना है। ताकि इमरजेंसी के दौरान आप तक वे आसानी से पहुंच सकें। कैब एप्लिकेशन में शेयरिंग ट्रिप का ऑप्शन भी आता है।

नई दिल्ली। पूरे देश में इस समय नए साल के जश्न का माहौल है। नए साल के दौरान पार्टी ऑल नाइट होती है, जहां क्लब, पब, रेस्तरां आज सारी रात खुले हुए होते होंगे। ऐसे में बहुत से लोग पार्टी वाले स्थान पर पहुंचने और वहां लौटने के लिए कैब फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐसे में कैब का इस्तेमाल करते समय किन किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है उसके बारे में आपको यहां बताने जा रहे हैं, ताकि आपका नया साल शुभ रहे।

कैब में बैठते ही तुरंत करें ये काम

देर रात हो गई है और आप अपने घर सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे गाड़ी के नंबर की तस्वीर और अपने गाड़ी का लाइव ट्रिप शेयरिंग को अपने किसी करीबी को अपडेट करते रहना है। ताकि, इमरजेंसी के दौरान आप तक वे आसानी से पहुंच सकें। कैब एप्लिकेशन में शेयरिंग ट्रिप का ऑप्शन भी आता है, जिसको सेंड पर आपके रियल टाइम लोकेशन के बारे में आपके घर वालों को पता रहेगा।

बीच-बीच में लोकेशन को चेक करते रहें

अगर आप नए साल पर या फिर उसकी पूर्व संध्या पर कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कैब में बैठने के बाद अपनी रूट को चेक करते रहना होगा, इसके अलावा कैब एप्लिकेशन को चेक करते रहना होगा, ताकि आपको पता रहे कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है और गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा इसका अंदाजा आप लगा सकें।

इसके अलावा, आपको एहतियाती उपाय के रूप में कैब बुक करने से पहले ग्राहक सेवा या सुरक्षा लाइनों के लिए फ़ोन नंबर सुनिश्चित करना चाहिए। इन नंबरों का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है, जैसे सेवा या फीडबैक के संबंध में शिकायत दर्ज करना।

होंडा हो या मारुति, कम खर्च में भी फर्राटे से दौड़ेगी आपकी कार, अपनाएं ये तरीका

कार लेने का सपना हर किसी का होता है। लेकिन कार लेने तक ही नहीं उसकी मेंटेनेंस में भी काफी खर्च आता है। अगर आप अपने लिए कोई लो मेंटेनेंस वाली कार खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लिस्ट लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। गाड़ी छोटी हो या बड़ी पर लोगों के भावों से जुड़ी रहती है। कार खरीदना आसान होता है पर उसकी मेंटेनेंस काफी महंगी होती है। अगर आप अपने लिए कोई लो मेटनेस वाली कार खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए उन गाड़ियों की लिस्ट लेकर आ रहे हैं। अगर आप अपने लिए एक ऐसी गाड़ी लेते हैं जिसकी सर्विसिंग, पाट्र्स या ईकानमी कम है तो आपको मेंटेनेंस के नाम पर ही साल भर में हजारों रुपये खर्चने पड़ते हैं।

Hyundai Grand i10 Nios

भारतीय बाजार में हुंडई ग्रांड i10 Nios 998सीसी डिसप्लेसमेंट में 4 सीटर गाड़ियों में सबसे किफायती कार है। इसकी कीमत भारतीय बाजार में 5.48 लाख रुपये से शुरु होती है। ये कार पहले साल में औसतन सिर्फ 1475 रुपये ही खर्च कराती है। 5 साल या 50 हजार किलोमीटर की बात करें तो ये सिर्फ खर्च में 16 हजार रुपये तक पहुचता हैं।

Maruti Suzuki Dzire

भारतीय बाजार में मारुति की कार को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इसका एक लीटर की एवरेज पर 24 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।इसकी मेंटेनेंस कास्ट की बात करें तो 1197 सीसी डिस्प्लेसमेंट वाली ये 5 सीटर कार पहले साल में सिर्फ 1892 रुपये का खर्च लेती है। पांच साल या 50,000 किलोमीटर में यह आंकड़ा मात्र 25 हजार रुपये ही होता है। मारुति सुजुकी डिजायर सिर्फ 6 लाख 24 हजार से शुरु होती है।

Tata Nexon

अब बात स्टाइल और पावर की करें तो इसमें इस कार का कोई जवाब नहीं है। ग्लोबल NCAP से सेफ़्टी में 5 स्टार रेटिंग जीतने वाली टाटा नेक्सन किसी भी कार में पीछे नहीं है। 1197 सीसी की टाटा नेक्सन में पहले साल या 15 हजार किलोमीटर में पहली सर्विस पर सिर्फ 3350 रुपये लगते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 7.70 लाख रुपये से शुरू होती है।

Honda Amaze

सेडान कार की करें तो होंडा अमेज का अपना ही नाम है। ये 1199 सीसी डिस्प्लेसमेंट की होंडा अमेज सिर्फ 6 लाख 63 लाख से शुरू होती है। इसकी पहली सर्विस 6 महीने या 10 हजार किलोमीटर पर होती है। जिसका खर्च मात्र 1298 हजार रुपये आता है।

Renault Triber

ये एक 7 सीटर कार है। इंडियन मार्केट में ये सबसे किफायती कार में से एक है। शानदार स्टाइल के साथ ये 998 सीसी के इंजन डिसप्लेसमेंट में भी यह गाड़ी अच्छी पावर जनरेट करती है। इसकी पहले साल की मेन्टीनेंस कॉस्ट कुल 1800 रुपये पड़ती है और वहीं पहले 5 साल या 50,000 किलोमीटर चलाने पर इसकी सर्विसिंग की कीमत 27000 के आस -पास होती है।

घर लाएं ये 6 लाख से कम कीमत वाली SUVs

भारतीय बाजार में एसयूवी की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप भी अपने लिए इस नए साल पर एक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज हम इन गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं।

नई दिल्ली। इंडियन मार्केट में स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स (SUV) कारों की डिमांड काफी अधिक है। खासकर कॉम्पैक्ट सेग्मेंट में लोग काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस सेगमेंट में नेक्सॉन, और मारुति ब्रेजा जैसे वाहन काफी बिके हैं इसके साथ ही निसान मैग्नाइट, रेनॉ किगर और टाटा पंच जैसे किफायती एसयूवी वाहन है जिनकी कीमत 6 लाख रुपये से कम की है। लोग इनकी कीमत और फीचर्स के कारण ही अधिक पसंद करते हैं। आइए एक नजर उनकी खूबियों पर डालते हैं।

Nissan Magnite

यह कॉम्पैक्ट एसयूवी में 1.0-लीटर नेचुरल एस्पायर्ड पेट्रोल मैनुअल (72PS की की पावर और 96 Nm का टॉर्क) 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मैनुअल (100PS पावर और 160Nm टॉर्क) और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल सीवीटी इंजन के साथ इंडियन मार्केट में आती है। इसमें 8 इंच टच स्क्रीन, 7 इंच टीएफटी के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, पुश-बटन स्टॉप/स्टार्ट, जेबीएल साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए ASEAN NCAP टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पर डायनेमिक्स कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, एबीएस, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर है। इसकी कीमत 5.97 लाख रुपये है। ये माइलेज 20.0 kmpl का देती है ।

Renault Kiger

भारतीय बाजार में Renault Kiger की RXT(O) वैरिएंट अब 1.0-लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल या सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है। पहले ये कार 1.0 लीटर के नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है। इसे फिर से अपडेट किया गया था। इसका इंजन 72PS की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें

Renault Kiger की RXT(O) वैरिएंट अब 1.0-लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन और मैनुअल या सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आती है. पहले ये कार 1.0 लीटर के नेचुरली 8 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कारप्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, पुश-बटन स्टॉप/स्टार्ट, जेबीएल साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल जैसे खास फीचर्स दिए गए है। इस कार की कीमत 5.99 लाख रुपये है।

TATA Punch

एसयूवी में लोगों को ये कार काफी पसंद आती है। इसमें 1.2 लीटर के पेट्रोल -इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो 86PS की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट जनरेट करता है। इसे 5 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फीचर्स के तौर पर इस कार में 7 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, ऑटो एयर कंडीशनिंग, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, रियर डिफॉगर, रियर पार्किंग सेंसर, एक रियर-व्यू कैमरा और आईएसओफिक्स एंकर मिलता है। इसे सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 6 लाख रुपये है।

अमीरों पर भारी टैक्स लगाओ

भारत डोगरा

इस रिपोर्ट के मुताबिक अरबपतियों के मुनाफे पर एकबारगी 20 प्रतिशत टैक्स लगाने से (2017-21 के दौरान) 1.8 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकते थे। यह धनराशि एक वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में 50 लाख अध्यापकों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त है।

बेशर्मी से केन्द्रित होती पूंजी और व्यापक रूप से फलती-फूलती गरीबी ने हमारे यहां जिस तरह की अश्लील गैर-बराबरी को खड़ा कर दिया है उससे निपटने की तजबीज आखिर कौन देगा? ऑक्सफैम सरीखे वैश्विक एनजीओ मानते हैं कि अकूत सम्पत्ति के मालिकों पर भारी टैक्स लगाकर स्थिति को समतल किया जा सकता है। प्रस्तुत है वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम में इसी हफ्ते की शुरुआत में जारी ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर यह लेख। सबसे धनी केवल 21 भारतीय अरबपतियों के पास कुल 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। यह तथ्य ख्यात वैश्विक एनजीओ ऑक्सफैम की रिपोर्ट से उजागर हुआ है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हर साल आयोजित होने वाले वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम (16 से 20 जनवरी 2023) में पहले दिन जारी की जाने वाली इस साल की 'सरवाईवल ऑफ दि रिचेस्ट : दि इंडिया स्टोरी' रिपोर्ट में विषमता संबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण आंकड़ों के साथ बताया गया है कि कोविड महामारी के आरंभ होने से नवंबर 2022 तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 121 प्रतिशत बढ़ी है। वास्तविक अर्थों में यह 3608 करोड़ रुपए प्रति दिन, यानी 2.5 करोड़ रुपए प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ी है। केवल 5 प्रतिशत भारतीयों के पास देश की संपत्ति का 60 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत के पास देश की संपत्ति का मात्र 3 प्रतिशत हिस्सा है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति की संपत्ति वर्ष 2022 में 46 प्रतिशत बढ़ी है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक अरबपतियों के मुनाफे पर एकबारगी 20 प्रतिशत टैक्स लगाने से (2017-21 के दौरान) 1.8 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए जा सकते थे। यह धनराशि एक वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में 50 लाख अध्यापकों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2012-2021 के दौरान भारत में जो संपत्ति निर्मित हुई है, उसका 40 प्रतिशत ऊपर की मात्र एक प्रतिशत जनसंख्या को गया है, जबकि नीचे की 50 प्रतिशत जनसंख्या को मात्र 3 प्रतिशत हिस्सा मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अरबपतियों की संख्या वर्ष 2020 में 102 से बढक़र वर्ष 2022 में 166 हो गई। भारत के 100 सबसे धनी लोगों की कुल संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जिससे 18 महीने का केन्द्रीय बजट बन सकता है। ऑक्सफैम (इंडिया) के सीईओ अमिताभ बेहर ने

कहा, 'जहां देश भूख, बेकारी, महंगाई व स्वास्थ्य आपदाओं से जूझ रहा है, वहां भारत के अरबपति अच्छा कमा रहे हैं। भूख से त्रस्त भारतीयों की संख्या वर्ष 2018 में 19 करोड़ थी, वर्ष 2022 में 35 करोड़ हो गई। कोविड के व्यापक दुख-दर्द को देखते हुए भारतीय सरकार को निर्धनता व अन्याय के विरुद्ध बड़े कदम उठाने चाहिए थे, पर यह नहीं हो सका व धनी वर्ग पर अधिक ध्यान दिया गया।' रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे धनी 10 भारतीयों की कुल संपत्ति 27 लाख करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष से इसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह संपत्ति स्वास्थ्य व आयुष मंत्रालयों के 30 वर्ष के बजट, शिक्षा मंत्रालय के 26 वर्ष के बजट व मनरेगा के 38 वर्ष के बजट के बराबर है। रिपोर्ट कहती है कि आय व संपत्ति की विषमता बढऩे के बीच भारत के गरीब लोगों को दुख-दर्द से राहत नहीं मिल पा रही है। सबसे अधिक, 22.8 करोड़ गरीब लोग इसी देश में हैं। अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव, खाद्यों व ऊर्जा कीमतों में वृद्धि से भी वे प्रभावित हैं। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए अपने प्रस्तुतीकरण में बताया है कि वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 65 प्रतिशत की मौतें कुपोषण के कारण हुईं।

भूख से प्रभावित भारतीयों की संख्या वर्ष 2018 में 19 करोड़ थी, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 35 करोड़ तक पहुंच गया। 70 प्रतिशत भारतीय अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं व इस अभाव से जो रोग जुड़े हैं उनसे एक वर्ष में 17 लाख मौतें होती हैं। इतना ही नहीं, यदि जनसंख्या के निचले 50 प्रतिशत हिस्से को देखें तो राष्ट्रीय आय में उसका हिस्सा मात्र 13 प्रतिशत रह गया है, जबकि संपत्ति में उसका हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत भर है। इतनी अधिक विषमता भारत जैसे देश में और भी चिंताजनक है जहां अधिकांश व्यक्तियों के रोजगार सुरक्षित नहीं हैं, जिनमें निश्चित वेतन व सामाजिक सुरक्षा होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2021 में औसतन प्रतिदिन 115 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं व महंगाई के कारण परिवारों का कर्ज बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2022 में, जून के अंत तक देश में व्यक्तिगत कर्ज 35.2 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ गया था। इसी समय ब्याज दर बढऩे लगी व खुदरा स्तर पर महंगाई 7.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार अल्प-विकसित व विकासशील देशों में आय विषमता में जो तेज वृद्धि हुई है, उसे समतावादी कर-नीति से ठीक किया जा सकता है व अमीरी से हो रहे लाभ का बेहतर वितरण भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

सबसे धनी लोगों की संपत्ति पर कर लगाने का समर्थन आक्सफैम वर्षों से करता रहा है। देश के सबसे धनी व मलाईदार तबके द्वारा अत्यधिक संपत्ति संचयन होता है जिस पर कर लगाने से सामाजिक क्षेत्रों को तेजी से आगे ले जाने के लिए अधिक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। वेलर व राव (2010) ने 'समतावादी कर नीति व आर्थिक स्थिरता' शीर्षक के अनुसंधान पत्र में लिखा है कि ऐसी नीति समता व स्थिरता के लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करती है। भारत व चीन जैसे देशों में कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 से 15 प्रतिशत के बराबर है जो पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि निर्धन वर्ग पर कर का बोझ कम करने से वस्तुओं व सेवाओं पर खर्च बढ़ता है व अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जबकि कारपोरेट को मिली कर की छूट का लाभ प्रायः धनी वर्ग तक सिमट कर रह जाता है। अमिताभ बेहर के मुताबिक धनी वर्ग के पक्ष में खड़ी व्यवस्था में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं, अनौपचारिक क्षेत्र के मेहनतकश जैसे सीमांत के लोग बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि धनी वर्ग पर टैक्स बढ़ाकर उनसे समुचित हिस्सा प्राप्त किया जाए। हम वित्तमंत्री से अपील करते हैं कि वे संपत्ति कर व इनहेरिटेंस टैक्स जैसे टैक्स लाएं जिससे विषमता कम हो। आक्सफैम ने वित्तमंत्री से संस्तुतियां की हैं कि ऊपर के एक प्रतिशत धनी व्यक्तियों की संपत्ति पर स्थाई तौर पर कर लगाना चाहिए व अत्यधिक धनी व्यक्तियों से अधिक कर प्राप्ति पर समुचित ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ निर्धन व निम्न-मध्यम वर्ग के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम करनी चाहिए व विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार स्वास्थ्य के लिए आवंटन को वर्ष 2025 तक जीडीपी का 2.5 प्रतिशत कर देना चाहिए ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य मजबूत हो सके व लोगों पर बोझ कम हो सके ताकि वे स्वास्थ्य संकट का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों व क्षेत्रीय आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो विषमताएं हैं, उन्हें दूर करना चाहिए। जिला अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कालेज खोलने चाहिए, विशेषकर पर्वतीय, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं व स्वास्थ्यकर्मियों की कमी न रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सरकारी अस्पतालों को बेहतर व मजबूत करना चाहिए। वहां पर्याप्त डाक्टरों व अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की व्यवस्था व जरूरी साज-सामान उपलब्ध हो ताकि उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा तीन किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हो सके। शिक्षा के बजट आवंटन के बारे में मान्यता है कि यह जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मान्यता मिली है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को योजनाबद्ध ढंग से आवंटन बढ़ाना चाहिए। शिक्षा में मौजूद विषमताओं को दूर करने के लिए इसके अनुकूल कार्यक्रमों को बढ़ाना चाहिए। -

संपादक की कलम से

हिंदू निशाने पर

आजकल टीवी चैनलों पर एक आध्यात्मिक-सा चेहरा छाया हुआ है। हालांकि वह खुद को न तो भगवान, संत-सिद्ध और न ही कोई चमत्कारी पुरुष मानते हैं। वह सिर्फ बालाजी हनुमान के भक्त हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ करते हैं। वह कैंसर, लकवा, पोलियो, एड्स सरीखी गंभीर बीमारियों के इलाज का भी दावा करते हैं। क्या अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर तालाबंदी कर दी जाए? अलबत्ता वह डॉक्टर से सलाह लेने का परामर्श भी लोगों को देते हैं। बीते कुछ दिनों से टीवी चैनलों पर आध्यात्मिक महाराज, उनके कथित 'दिव्य दरबार' और भूत-पिशाच से परेशान लोगों को दिखाया जा रहा है। आध्यात्मिक पुरुष के लंबे-लंबे साक्षात्कार प्रसारित किए जा रहे हैं। महाराज बार-बार ताली बजाकर कुछ ठोंकते हैं और फिर आह्वान करते हैं कि हिंदुओ! जाग जाओ। तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनवा कर दिखाऊंगा। यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे की पैरोडी लगता है, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिवस था। महाराज आगे कहते हैं कि हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं। भारत अकबर का नहीं, संन्यासियों का देश है। सनातन धर्म को चुनौतियां और धमकियां दी जा रही हैं। बालाजी हनुमान और प्रभु राम के भक्त चमत्कारी हैं या पाखंडी हैं अथवा कोई चालबाजी है, हम न तो पुष्टि कर सकते हैं और न ही भत्र्सनापूर्ण खंडन कर सकते हैं। उनके कथित दरबार में लाखों की भीड़ उमड़ती है। कोई तो श्रद्धा या आस्था होगी! लोग उन्हें 'भगवान' का प्रतीक और 'अंतर्यामी' मानते हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर के नेता उनके सार्वजनिक समर्थक हैं और दर्शनार्थी के तौर पर नमन भी करते हैं। लेकिन साधु-संत उन्हें लेकर विभाजित हैं।

सारांश यह है कि एक चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और सनातनी आस्थाओं का पैरोकार बनकर उभरा है। उनका आग्रह है कि 'रामचरितमानस' को 'राष्ट्रीय ग्रंथ' घोषित किया जाए। इसके समानांतर उप्र के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद स्वामीप्रसाद मौर्य ने 'रामचरितमानस' पर पाबंदी चस्पा करने की मांग की है। वह इस महाकाव्य को 'पिछड़ा, दलित, महिला-विरोधी' करार दे रहे हैं। उनकी मांग है कि चमत्कार के नाम पर उस 'पाखंडी, ढोंगी' को जेल में ठूंस देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कथित चमत्कार या भूत-प्रेत का इलाज अथवा धर्मान्तरण का संविधान में कोई स्थान नहीं है। संविधान धार्मिक आस्था और पूजा-पद्धति का अधिकार देता है, लेकिन वह आध्यात्मिक पुरुष जादू-टोना करता है। उप्रही नहीं, बिहार में लालू की पार्टी के एक नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि 'रामचरितमानस' में बहुत कुछ कचरा भी है, लिहाजा उसे साफ करने की जरूरत है। विडंबना है कि एक बौना-सा नेता महान तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में संशोधन की बात कर रहा है! बहरहाल यह हमारे देश के पावन और गरिमामय 'गणतंत्र दिवस' का भी दौर है। इसी दौर में हमारा संविधान लागू किया गया था। संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की गई है, तो पूजनीय सीता-राम का चित्र भी संविधान-पुस्तक में छापा गया है। भारत हिंदुओं का ही नहीं, पूरे विश्व का देश है। हम तो 'वसुधैव कुटुम्बकम' की सोच के पक्षधर हैं। 'हिंदू राष्ट्र' की धारणा और घोषणा ही असंवैधानिक है। यह भ्रम और दुष्प्रचार है। वह कथित चमत्कारी पुरुष कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लोकप्रिय आयोजनों के मद्देनजर सनातन धर्म को गाली क्यों दी जाए? हिंदू ही हिंदू के खिलाफ क्यों खड़ा है? हर बार हिंदू ही निशाने पर क्यों रहता है? डॉ. राममनोहर लोहिया कहते थे कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हरेक गांव में राम से जुड़ी चार कहानियां मिल जाएंगी। रामलीला का मंचन मिलेगा और औसत घर में 'रामचरितमानस' का पाठ होता दिखेगा। फिर यह फैशन लगातार जोर क्यों पकड़ता रहता है कि 'रामचरितमानस' की व्याख्या की जानकारी न होते हुए भी कुछ अविवेकी लोग इस पवित्र ग्रंथ के साथ 'नफरत' नत्थी कर रहे हैं?

भारत में 26 जनवरी 1950 से इस तारीख को गणतंत्र दिवस के रूप में उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मगर 26 जनवरी को सिर्फ गणतंत्र दिवस के लिए ही नहीं बल्कि भारत और विश्व इतिहास में कई बड़ी प्रमुख घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। 26 जनवरी ही वो तारीख है जिस दिन भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। इसके अलावा विश्व इतिहास में इस दिन हुमायूं की मौत, शांति संधि, अनाक्रमण संधि के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बिल गेट्स को 'नाइट' की उपाधि भी इसी दिन मिली थी।

भारत में 26 जनवरी की प्रमुख बड़ी घटनाएं...

1931- 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी रिहा किए गए।

1950- भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ।

1950- स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया और डा. राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने।

1963- मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया।

1972- युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर 'अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक' की स्थापना की गई।

1981- पूर्वोत्तर भारत में हवाई यातायात सुगम बनाने को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा वायुदूत प्रारम्भ हुई।

1982- पर्यटकों को विलासितापूर्ण रेल यात्रा का आनंद दिलाने के लिए भारतीय रेल ने 'पैलेस ऑन व्हील्स' सेवा शुरू की।

2000- कोंकण रेलवे परियोजना पूर्ण हुई और प्रथम यात्री गाड़ी चलाई गयी।

2001- गुजरात के भुज में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए।

2003- ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए।

2008- 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने परेड की सलामी ली।

2008- एन.आर. नारायणमूर्ति को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'द ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑवर' से सम्मानित किया गया।

इनसान का घटता कद

हमारे यहां शोध करने के लिए दर्जनों दिलचस्प विषय हैं। हमारे शोध पर अमल कर दुनिया धन्य होती है लेकिन यह विदेशी अजीब विषयों पर शोध करते रहते हैं। सुसंस्कृत, सभ्य धरती का सम्मानित नागरिक होने के नाते मुझे हैरानी होती है कि उन्हें हमारे जैसे बढिय़ा विषय क्यूं नहीं मिलते। दुनिया भर में इंसानियत ही नहीं हैवानियत पर भी खतरा मंडरा रहा है और वे शोध कर बता रहे हैं कि बारह हज़ार साल पहले जब मानव शिकार से खेती की और उन्मुख हुआ तो किसान बनने से उसका कद औसतन डेढ़ इंच घट गया। यह स्पष्ट माना जा सकता है कि उस समय इंसान के पास आज जितनी बुद्धि होती तो वह शिकारी यानी मांसाहारी से किसान या शाकाहारी होने की न सोचता। दिलचस्प यह है कि यह अध्ययन मानव कंकाल के डीएनए पर आधारित है। पता नहीं यह जीवित लोगों की भूख पर ज़्यादा ध्यान क्यूं नहीं देते। कहते हैं खेतों में उगने वाले खाद्य से कम पौष्टिकता मिलती थी और किसान हो रहा इंसान बीमार हो जाता था, इसलिए उसका कद कम हो गया।

बाद में खेती के क्षेत्र में विकासजी आए, उनकी मेहनत से काफी फर्क पड़ा। वह बात और है कि हमारे देश में मांसाहारी बढ़ रहे हैं और दुनिया में कम हो रहे हैं। वैसे तो हमारे यहां अपना कद बढाने और दूसरे का कद घटाने के अनेक रास्ते हैं जिन पर पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कद बढ़ाने वाले शान से इठला कर विचरते हैं। इस बारे विदेशियों को हमसे सीखना चाहिए। हम विश्वगुरु भी तो हैं न। हम उन्हें सिखा सकते हैं कि बहुत से लोगों का कद एक दम कैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दो अलग अलग कद वालों को आपस में कैसे भिड़ाया या लड़वाया जा सकता है। हमारे यहां सभ्यता, नैतिकता, सद्भाव ज़्यादा फैल जाने के कारण कद ऊंचा हो जाता है या कर दिया जाता है। किसी का बड़ा कद रसातल में भेजकर उसे उदास कैसे किया जाता है, लोकतंत्र के काबिल और अनुभवी यंत्र, तंत्र, मंत्र और षड्यंत्र सक्रिय रहते हैं। यदि भाग्य का शर्बत मिल जाए तो इंसान का कद नौवें आसमान पर पहुंच जाता है। कद की और बात करें तो हमारे यहां यह पता नहीं चलता कि अमुक छोटे कद का आदमी ज़मीन के अंदर कितना है। एक दूसरे का कद एक समान समझने की बुरी आदतें हमें नहीं है। सामने वाले का कद अपने से कम समझना हम अपना नैतिक कत्र्तव्य मानते हैं। हमारे यहां तो जाति, धर्म और धन के आधार पर भी कद बड़ा और छोटा कर दिया जाता है। इंसानियत, ईमानदारी व अनुशासन के लम्बे कद को राजनीति, पाखण्ड और भेदभाव की तलवारों से पल भर में ज़मीन पर ला देते हैं। विदेशियों के सर्वे मुझे अध्ययन और शोध करने के लिए उकसाते हैं ताकि कुछ सचाइयां उगा सकूं, मगर हर तरह से छोटे कद का आदमी मैं, क्या कर सकता हूं। आदमी इस बात को माने या न माने, मेरे आकलन के हिसाब से इंसान का कद दिन प्रतिदिन घट रहा है।

प्रभात कुमार

वर्ष-2023 में उत्तर प्रदेश में बहेगी विकास और निवेश की गंगा

वर्ष-2023 उत्तर प्रदेश के विकास और निवेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। फरवरी में आयोजित होने जा रही इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से इस वर्ष आने वाले अभूतपूर्व निवेश से जहाँ प्रदेश के युवाओं को विविध क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे वहीं किसानों की आय भी बढ़ने जा रही है। भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में भी इस समूह के देश के विभिन्न मंत्रियों व अधिकारियों की बड़ी बैठकें होने जा रही है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निवेशकों व पर्यटकों को आकर्षित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहती और उसका मास्टर प्लान भी तैयार हो चुका है। आगामी वर्ष 2023 में प्रदेश में कई मेगा इवेंट होने जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट का आयोजन करने का दायित्व भी प्रदेश को मिला है।

प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुहिम चलाई और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब तक के समाचारों के अनुसार फरवरी में राजधानी लखनऊ में आयोजित होने जा रही समिट में 52 से अधिक निवेशक व कंपनियां हिस्सा लेंगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने विदेशों में रोड शो किये तथा इस दौरान "एक जिला -एक उत्पाद" जैसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी किया किया।

प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए अलग-अलग देशों में गए प्रतिनिधि मंडलों को अच्छी सफलता मिली है। अमेरिका, नीदरलैंड, यूएई सहित खाड़ी के कई देश प्रदेश में भारी भरकम निवेश के लिए तैयार हो रहे हैं। विदेशी निवेशकों में जिस प्रकार का आकर्षण दिख रहा है उससे साफ हो गया है कि विदेशों में भी योगी मॉडल लोकप्रिय हो गया है। आस्ट्रेलिया और बेल्जियम से निवेश का कॉरिडोर बन रहा है। ब्राजील के निवेशक भी प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं। आस्ट्रेलिया के निवेश प्रदेश में डिफेंस, वाटर रिसोर्स हेल्थ और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उत्साहित हुए। बेल्जियम में आयोजित रोड शो में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की ओर से बैठक में ब्रुसेल्स में एशिया और पैसिफिक डिविजन के हेड और एमडी एडवांस बमनस्टेस भी उपस्थित रहे।बैठक के बाद प्रदेश सरकार में औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि विदेशी निवेशकों के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ब्राजील में निवेशकों से मुलाकात कर कृषि, डेयरी, आईटी व फार्मा सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तलाशी हैं। दक्षिण कोरिया और जापान आदि देशों के निवेशकों में भी प्रदेश में निवेश करने का उत्साह दिखा। सिंगापुर की कंपनियों ने 8500 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। नीदरलैंडस से 1050 करोड़.के प्रस्ताव मिले हैं। जापान ने मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश को लेकर रूचि दिखाई है। कनाडा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भागीदार बनना चाहता है। स्वीडन की कंपनियों ने हथियारों का प्लांट लगाने की इच्छा जताई है। जिसमें स्वीडन की कंपनियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर 15 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। ये कंपनियां फिल्म सिटी, रिटेल टूरिज्म वेस्ट मैनजमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश करने को तैयार हैं। अर्जेंटीना के निवेशकों के साथ भी सार्थक चर्चा हुई और कृषि व आईटी आदि क्षेत्रों के लिए निवेशकों ने उत्साह दिखाया है। मेक्सिको, लंदन और जर्मनी में हुए रोड शो में प्रदेश सरकार द्वारा दी गई प्रस्तुति से निवेशकों में विशेष उत्साह देखने को मिला है।

हर साल 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस

2023 Republic Day India भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। यह दिन भारत के इतिहास में एक अलग अहमियत रखता है। इस साल देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस दिन के इतिहास और इसके महत्व के बारे में-

देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्योहार की अपनी अलग खासियत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो आज हम आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस के इतिहास और इसके महत्व के बारे में-

26 जनवरी को राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं तिरंगा

गणतंत्र दिवस का इतिहास

दरअसल, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया है। 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आजादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शूरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवंबर, 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी, 1950 को पूरे देश में

यह संविधान लागू किया गया था।

26 जनवरी का महत्व

26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, यह सवाल लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा। संविधान लागू करने के लिए इस तारीख को चुनने का भी एक खास मकसद था। दरअसल, 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान

आजादी के साथ ही देश के लिए एक संविधान की जरूरत भी महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इस सभा ने 9 दिसंबर, 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे। डॉ. अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल, 11 माह, 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इनसाइड

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जारी रहेगी महंगाई के खिलाफ जंग

रूस-यूक्रेन युद्ध ने महंगाई को हवा दी, जिसने वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया और कई वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने इस साल मई के बाद से अल्पकालिक उधार दर (रेपो) में 2.25 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की है।

नई दिल्ली। इस साल ज्यादातर समय महंगाई के आरबीआई के संतोषजनक स्तर छह प्रतिशत से ऊपर रहने के बाद खुदरा मुद्रास्फीति धीरे-धीरे नरम पड़ रही है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति को और कम करने के प्रयास जारी रहेंगे। वर्ष के दौरान कच्चे तेल और खाद्य तेलों, दालों तथा सब्जियों की कीमतों में तेजी के चलते मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। रूस-यूक्रेन युद्ध ने महंगाई को हवा दी, जिसने वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को बाधित किया और कई वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने इस साल मई के बाद से अल्पकालिक उधार दर (रेपो) में 2.25 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर लगभग तीन साल के उच्च स्तर 6.25 प्रतिशत पर पहुंच गई है। केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो से छह प्रतिशत के बीच रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वर्ष के दौरान कच्चे तेल और खाद्य तेलों, दालों तथा सब्जियों की कीमतों में तेजी के चलते मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने महंगाई को हवा दी, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया और कई वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने मई के बाद से नीतिगत दर रेपो में 2.25 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर लगभग तीन साल के उच्च स्तर 6.25 प्रतिशत पर पहुंच गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल में कहा था कि वैश्विक संकट, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, घरेलू उत्पादन कीमतों और मौसम संबंधी व्यवधानों के चलते मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है। वर्ष के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप सहित दुनिया भर के नियामकों के लिए मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती थी। मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पड़ा और जिंस कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 2016 में शुरुआत के बाद पहली बार आरबीआई ने सरकार को रिपोर्ट सौंपकर बताया कि जनवरी से लगातार तीन तिमाहियों में मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से अधिक क्यों रही। थोक मुद्रास्फीति नवंबर में 5.85 प्रतिशत तक गिरने से पहले सितंबर तक दहाई अंकों में थी। उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 6.6 प्रतिशत और मार्च तिमाही में घटकर 5.9 प्रतिशत रह जाएगी। रेटिंग फर्म इक्रा के अनुसार अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति में कमी आने की संभावना है।

सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के श्रमिक संगठन ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी

एनटीवी न्यूज

नईदिल्ली। मंच ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन में फायदे में चल रहे कार्यालयों सहित कई दफ्तरों को बंद करने की बात है। इसके अलावा कार्यालयों का विलय भी किया जाना है। उसने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1,000 कार्यालय पहले ही बंद हो चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के एक वर्ग ने चार जनवरी को हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ये कर्मचारी इन कंपनियों के प्रस्तावित पुनर्गठन के खिलाफ हैं। साधारण बीमा कंपनियों के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच (जेएफटीयू) ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित पुनर्गठन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कमजोर करेगा। मंच ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन में फायदे में चल रहे कार्यालयों सहित कई दफ्तरों को बंद करने की बात है। इसके अलावा कार्यालयों का विलय भी किया जाना है। उसने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1,000 कार्यालय पहले ही बंद हो चुके हैं।

इनमें से ज्यादातर मझोले और छोटे शहरों (टियर-2 और टियर-3) में थे। श्रमिक संगठनों के मंच ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के कार्यालयों के बड़े पैमाने पर बंद होने और विलय होने से न केवल पॉलिसीधारकों पर बल्कि आम नागरिकों पर भी असर पड़ रहा है। मंच ने कहा कि इससे निजी बीमा कंपनियों को मझोले और छोटे शहरों के बाजार पर कब्जा करने के लिए अनुचित लाभ मिल रहा है। उसने कहा कि इन सबको देखते हुए चार साधारण बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यूइंडियाएश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और जीआईसी री के करीब 50,000 कर्मचारी चार जनवरी को एक दिन की हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं।

बजट के बाद उठेगा या गिरेगा शेयर बाजार? जानिए क्या रहा है ट्रेंड

एनटीवी न्यूज

बजट से पहले शेयर बाजार में अक्सर गिरावट देखने को मिलती है। यह औसतन एक फीसदी की होती है। पिछले 10 साल में बजट के दिन 5 बार बाजार गिरे हैं। बजट के दिन यानी 1 फरवरी को ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक यूएस फेड का ब्याज दरों को लेकर फैसला आएगा।

नई दिल्ली : इतिहास बताता है कि बजट से पहले कारोबार थोड़ा दब जाता है। एक आकलन के मुताबिक, बजट के एक महीने पहले जो औसत गिरावट आती है, वो एक फीसदी की है। 2003 के बाद से ये बात देखी जा रही है। ठीक बजट के दिन की बात करें तो पिछले 10 साल में Sensex और Nifty पांच बार गिरे। बाकी समय वे चढ़कर बंद हुए। बाजार के नजरिये से 2020 में बड़ा उतार-चढ़ाव रहा। तब बजट के दिन शेयर बाजार में 11 बरसों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। उसके तुरंत बाद कोरोना संकट के कारण बाजार में बड़ी गिरावट आई थी। ये इतनी जबरदस्त रही कि Sensex 23 मार्च, 2020 को 25,981 पर आ गया था। लेकिन हालात बड़ी तेजी से बदले। उसके बाद से अभी तीन साल भी पूरे नहीं हुए और आज Sensex 60 हजार से ऊपर है।

बाजार के लिए पॉजिटिव रहे पिछले 2 बजट

पिछले दो बजट को देखें तो शेयर बाजार के लिए ये काफी पॉजिटिव रहे। इसकी वजह ये है कि सरकार के उपायों की वजह से इकॉनमी को सहारा मिला, जो कोरोना की मार से बदहाल हो गई थी। बजट से पहले हो सकता है कि बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहे। जानकार कहते हैं कि किसी भी तरह का पैनिक घाटा पहुंचा सकता है। गलत फैसला लेकर अगर कोई स्टॉक बेचते हैं तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है।

बजट से क्या चाहते हैं निवेशक?

शेयर बाजार से जुड़े लोगों की कई और डिमांड भी सामने आ रही हैं। ये तबका चाहता है कि सरकार अपना खर्च बढ़ाए। इससे प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा होगा और इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी। खास तौर से इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने से बड़ा फर्क आएगा। इसके साथ ही सरकार अपनी आमदनी और खर्चे के अंतर को जल्दी से जल्दी पाटे। टैक्स सिस्टम में भी कोई बड़ा बदलाव न हो। अगर बजट में किसी तरह की इनकम टैक्स छूट दी जाती है तो इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। महंगाई अगर तेज हुई तो इससे शेयर बाजार के सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है।

टैक्स में मिले राहत

टैक्स की बात चली है तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले सबसे ज्यादा परेशान दिखते हैं कैपिटल गेंस टैक्स से। उनकी शिकायत पर गौर कीजिए। आप अक्सर सुनते होंगे फलां शेयर ने निवेशकों को पांच साल में 100 फीसदी या इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर ने जो एक्चुअल रिटर्न दिया है, वह पूरा नहीं मिलता है। उस पर टैक्स लग सकता है। 2018 के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को बहाल किया गया था। इक्विटी यानी शेयरों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता था। कैपिटल गेन्स टैक्स दो तरह के होते हैं- शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। कौन सा टैक्स लगेगा, यह शेयरों के होल्डिंग पीरियड के अनुसार तय किया जाता है। किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर उससे होने वाली आय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के तहत आती है यानी वह टैक्सेबल है। इस पर बजट में राहत की उम्मीद की जा रही है।

गेहूं का रकबा 30 दिसंबर तक 3.59 प्रतिशत बढ़ा, उत्पादन बेहतर रहने की संभावना

नई दिल्ली। शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई अक्टूबर से शुरू हो गई थी। मक्का, ज्वार, चना और सरसों अन्य प्रमुख रबी फसलें हैं। इन फसलों की कटाई अगले साल मार्च/अप्रैल में शुरू होगी।

गेहूं का कुल रकबा, एक साल पहले की तुलना में 3.59 प्रतिशत बढ़कर 325.10 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। रबी फसलों की बुवाई अब समाप्त होने की ओर है। शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुवाई अक्टूबर से शुरू हो गई थी। मक्का, ज्वार, चना और सरसों अन्य प्रमुख रबी फसलें हैं। इन फसलों की कटाई अगले साल मार्च/अप्रैल में शुरू होगी। ताजा आंकड़ों के अनुसार, किसानों ने फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) के मौजूदा रबी सत्र में 30 दिसंबर तक 325.10 लाख हेक्टेयर से भी अधिक रकबे में गेहूं की बुवाई की है, जबकि पिछले वर्ष यह रकबा 313.81 लाख हेक्टेयर था।

जिन राज्यों में बुवाई का रकबा अधिक रहा है, उनमें उत्तर प्रदेश (3.59 लाख हेक्टेयर), राजस्थान (2.52 लाख हेक्टेयर), महाराष्ट्र (1.89 लाख हेक्टेयर), गुजरात (1.10 लाख हेक्टेयर), बिहार (0.87 लाख हेक्टेयर), मध्य प्रदेश (0.85 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (0.66 लाख हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (0.21 लाख हेक्टेयर), जम्मू और कश्मीर (0.08 लाख हेक्टेयर), असम (0.02 लाख हेक्टेयर) और झारखंड (0.03 लाख हेक्टेयर) शामिल हैं। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रबी फसलों की बुवाई अब तक लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुवाई गन्ने की कटाई के बाद जनवरी में की जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि किसानों ने वर्ष 2023 में भी समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिलने की उम्मीद में अधिक रकबे में गेहूं की बुवाई की है। गेहूंउपज की संभावना अभी बेहतर दिखाई दे रही है और मंत्रालय को उम्मीद है कि मौसम की स्थिति अच्छी रहने पर रिकॉर्ड उत्पादन होगा। आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सत्र में 30 दिसंबर तक धान की बुवाई का रकबा भी बढ़कर 16.53 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो एक साल पहले की अवधि में 13.70 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह, समीक्षाधीन अवधि के दौरान 150.10 लाख हेक्टेयर के मुकाबले दालों का रकबा बढ़कर 153.09 लाख हेक्टेयर हो गया है।

इस रबी सत्र में अब तक कुल दलहन में से 105.61 लाख हेक्टेयर में चना बोया जा चुका है। आंकड़ों से पता चलता है कि मोटे और पौष्टिक अनाज का रकबा पहले के 44.85 लाख हेक्टेयर से मामूली बढ़कर 46.67 लाख हेक्टेयर हो गया है। तीस दिसंबर तक विभिन्न प्रकार के तिलहनों का कुल रकबा बढ़कर 103.60 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो एक साल पहले की अवधि में 94.96 लाख हेक्टेयर ही था। आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें से रेपसीड-सरसों का रकबा पहले के 86.56 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर 94.22 लाख हेक्टेयर हो गया है। नतीजतन, चालू रबी सत्र में 30 दिसंबर तक रबी फसलों का कुल रकबा 4.46 प्रतिशत बढ़कर 645 लाख हेक्टेयर पहुंच गया। एक साल पहले इसी अवधि में यह 617.43 लाख हेक्टेयर था।

सूत्रों का कहना है कि वाणिज्य मंत्रालय बजट में सोने के आयात पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव रखता है

सरकार ने यह कदम चालू खाता के घाटे में कमी लाने और सोने के बढ़ते आयात पर काबू पाने के इरादे से उठाया था। सोने पर बुनियादी सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत लगता है जबकि 2.5 प्रतिशत की दर से कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगता है।

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में सोने पर आयात शुल्क घटाए जाने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने गत जुलाई में सोने पर आयात शुल्क 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। सरकार ने यह कदम चालू खाता के घाटे में कमी लाने और सोने के बढ़ते आयात पर काबू पाने के इरादे से उठाया था। सोने पर बुनियादी सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत लगता है जबकि 2.5 प्रतिशत की दर से कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगता है।

इस तरह कुल प्रभावी आयात शुल्क 15 प्रतिशत हो जाता है। सूत्रों ने बताया कि रत्न एवं आभूषण उद्योग की मांगों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से आगामी बजट में इस तरह का प्रस्ताव रखने की मांग की है। सूत्रों ने कहा, वाणिज्य मंत्रालय ने रत्न-आभूषण के विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य उत्पादों पर भी आयात शुल्क में बदलाव की मांग रखी है। रत्न एवं आभूषणों के निर्यात से जुड़े हितधारक आयात शुल्क में कटौती की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं।

रत्न एवं आभूषण निर्यात प्रोत्साहन परिषद (जीजेईपीसी) के पूर्व चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा कि उद्योग ने एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में निर्यात को बढ़ावा देने वाले कदमों की घोषणा की उम्मीद लगाई हुई है। शाह ने कहा, सोने के आयात शुल्क में कटौती और आभूषण के लिए एक प्रगतिशील मरम्मत नीति आने से इस क्षेत्र को व्यापक लाभ होंगे। हम इस बात को लेकर भी आशांवित हैं कि कच्चे हीरे पर संभावित कराधान और प्रयोगशाला में हीरा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले बीज पर शुल्क को खत्म किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान देश से रत्न एवं आभूषण का निर्यात दो प्रतिशत बढ़कर 26.45 अरब डॉलर हो गया। इस दौरान सोने का आयात 18.13 प्रतिशत घटकर 27.21 अरब डॉलर पर आ गया। सोने का आयात कम होने से चालू खाते का घाटा कम करने में मदद मिलती है।

स्लीपर कोच वाली वंदे भारत, टिकट में सब्सिडी और नई ट्रेनें... रेल बजट में इस बार क्या मिलेंगी सौगातें?

मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। रेल यात्रियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सीनियर सीटीजंस रेल टिकट में फिर से सब्सिडी मिलने की उम्मीद लगा रहे है।

नई दिल्ली : रेल बजट (Rail Budget) से लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अपना पांचवां बजट पेश करेंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट को भी आम बजट (General Budget) से जोड़ दिया था। अब रेलवे के लिए भी पैसा इसी बजट से दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक केंद्र इस बार रेलवे बजट में बढ़ोत्तरी करने जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 20 फीसदी तक का इजाफा करेगी। इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25-30 फीसदी अधिक फंड की मांग की है। ऐसे में इस बार सरकार रेल मंत्रालय को बजट में करीब 2 ट्रिलियन रुपये का फंड दे सकती है। बजट से पहले रेलवे से जुड़े कई सेक्टरों में उत्साह का माहौल है। रेल यात्रियों की ओर से कई तरह की मांगें भी रही हैं।

चुनावों से पहले आखिरी पूर्ण बजट

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये अन्तिम पूरा बजट है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2023 में ही देश में 10 राज्यों चुनाव भी हैं। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही जम्मू-कश्मीर में भी इस साल चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले पेश होने वाले इस रेल बजट में केंद्र सरकार आम यात्रियों से जुड़ी कई नई रेल सुविधाओं का ऐलान कर सकती है। यह माना जा रहा है कि इस बार का रेल बजट चुनावी बजट साबित हो सकता है, विशेषकर उन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। इसलिए केंद्र सरकार उनके लिए कुछ विशेष ऐलान कर सकती है।

पिछले साल से 71% बढ़ी इनकम

हालांकि, रेल मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में अब तक 42,370 करोड़ रुपए अधिक राजस्व हासिल किया। पिछले साल से अगर इसकी तुलना करें तो इस साल रेलवे की इनकम 71 फीसदी तक बढ़ चुकी है। जबकि इससे पहले साल 2021 में 26 हजार 338 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसलिए सरकार ने आम लोगों को दी जाने वाली कई रिआयतों को बंद कर दिया था।

सीनियर सिटीजंस को फिर से मिले सब्सिडी

रेलवे की कमाई के मजबूत आंकड़े देखकर अब एक फिर तमाम तबकों के लोग सरकार से उस सब्सिडी फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक जिन्हें कोविड महामारी से पहले 50 फीसदी तक की छूट मिलती थी। इसे अब बंद कर दिया गया है। हालांकि, रेल मंत्रालय के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट देने की इस बजट में कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार अधिकतर निवेश रेलवे के आधुनिकीकरण में ही करेगा। रेलवे ट्रेनों के निर्माण के लिए बेहतर घरेलू इंफ्रास्ट्रक्च र का निर्माण करने पर भी ध्यान दे रही है। इसमें ट्रेनों के पहियों को लेकर विदेशी निर्भरता कम करने की भी योजना बनाई जा रही है।

वंदे भारत एक्सप्रेस पर रहेगा जोर

इस बार के बजट में स्लीपर सुविधा वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत 2.0 बनाने पर जोर दिया जा सकता है। अब इस ट्रेन में स्लीपर बर्थ भी लगाई जाएगी। इससे लंबी दूरी का करने वाले यात्रियों को बेहतरीन स्लीपर ट्रेन सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस की तरह काम करेगी जिसमें यात्रियों को स्लीपर एसी कोच की सुविधा भी मिलेगी। रेल बजट 2023 में 500 वंदे भारत, 35 हाइड्रोजन ट्रेन, 5000 एलएचबी कोच, 58000 वैगन के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय रेल योजना 2030

उल्लेखनीय है कि पिछले रेल बजट के ऐलान के दौरान वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की भी घोषणा की थी। इस योजना के तहत रेलवे के विकास के लिए प्लान तैयार किया गया। इसमें रेल सुविधाओं को नया रूप दिये जाने का ऐलान किया गया था। इसके लिए केंद्र ने एक लाख करोड़ के निवेश करने की बात की थी। दिसंबर 2023 तक रेलवे की बड़ी लाइन का 100 फीसदी विद्युतीकरण पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह टीयर-2 श्रेणी के दो शहरों और टीयर-1 श्रेणी के शहरों के बाहरी हिस्सों में मेट्रो रेल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय रेल 2030 तक दुनिया की पहली 100 फीसदी ग्रीन रेल सेवा हो जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस बार रेल बजट में हाइपरलूप तकनीक को अपनाने का ऐलान कर सकती है। इसमें यात्रियों को ले जाने वाले पॉड ट्यूब या सुरंगों के माध्यम से यात्रा की जाती हैं। ये तकनीक बुलेट ट्रेन से भी तीव्र है। साथ ही इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्च र को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है।

4,000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का टारगेट

हालांकि विजन 2024 की परियोजनाओं के तहत, दशक के उत्तरार्ध में, नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर को चालू करने के अलावा, भीड़भाड़ वाले मार्गों के मल्टीट्रैकिंग और सिग्नलिंग अपग्रेडेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही नया रेलवे ट्रैक भारतीय रेलवे के नए विजन डॉक्युमेंट का हिस्सा होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में करीब 4,000 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का टारगेट तय किया जा सकता है। नए ट्रैक ब्रिज को भी दोगुना यानी 50,000 करोड़ रुपये किया जा सकता है। अभी की कीमत के मुताबिक, सामान्य 1,00,000 किलोमीटर लाइन बिछाने पर करीब 15-20 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। आगामी रेल बजट में 7,000 किलो मीटर ब्रॉड गेज लाइन को इलेक्ट्रिफाई करने का भी ऐलान हो सकता है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन हो सकता है। 7,000 किलो मीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन से रेलवे के पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रिफाई करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

अंबेडकर-गांधी के आदर्शों का जिक्र, मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ, जानिए राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन की खास बातें

एनटीवी न्यूज

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के नाम संबोधन दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुर्मू ने कहा कि गांधीजी के सर्वोदय के आदर्शो को प्राप्त करना अभी बाकी है। उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि हमें घबराना नहीं है। इसके अलावा मुर्मू ने मोदी सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की।

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। द्रौपदी मुर्मू ने बाबासाहेब आंबेडकर और अन्य विभूतियों की ओर से प्रस्तुत भविष्य के मानचित्र का जिक्र करते हुए कहा कि हम काफी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं, लेकिन यह भी महसूस करते हैं कि गांधीजी के सर्वोदय के आदर्शों को प्राप्त करना, सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है। मुर्मू ने आगे कहा कि हम यह भी महसूस करते हैं कि गांधीजी के सर्वोदय के आदर्शों को प्राप्त करना, सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व की सबसे पुरानी और जीवंत सभ्यताओं में से एक है तथा उसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की चुनौतियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर और अन्य विभूतियों ने हमें एक मानचित्र तथा एक नैतिक आधार प्रदान किया और उस राह पर चलने की जिम्मेदारी हम सब की है। उन्होंने कहा, 'हम काफी हद तक उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे भी हैं लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि गांधीजी के सर्वोदय के आदर्शों को प्राप्त करना अर्थात सभी का उत्थान किया जाना अभी बाकी है।'

'हमने सभी क्षेत्रों में उत्साहवर्धक प्रगति हासिल की'

राष्ट्रपति ने कहा कि हमने सभी क्षेत्रों में उत्साहवर्धक प्रगति हासिल की है तथा सर्वोदय के मिशन में आर्थिक मंच पर भी प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तथा यह उल्लेख करना जरूरी है कि यह उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है।

कोविड-19 के वैश्विक प्रभावों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है।

संबोधन में कोविड-19 का जिक्र, सरकार के प्रयासों की तारीफ

राष्ट्रपति ने कहा कि शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुंची, फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावशीलता के बल पर हम इससे बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। मुर्मू ने कहा, 'अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब हमारी महामारी के प्रभाव से बाहर आ गए हैं। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । यह सरकार की तरफ से समय पर किए गए प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है।' उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जन सामान्य के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

सरकार की कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कई क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं और यह संतोष की बात है कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे, उनका भी योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेश किया गया है तथा कठिनाई में उनकी मदद की गई है। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर अमल करते हुए सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, जब हमारे देशवासी कोविड-19 की महामारी के कारण अकस्मात उत्पन्न हुए आर्थिक विरोध का सामना कर रहे थे।

पीएम गरीब कल्यायण योजना से हुआ गरीबों को लाभ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस सहायता की वजह से किसी को खाली पेट नहीं सोना पड़ा तथा गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 81 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते रहे। उन्होंने कहा कि इस सहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 के दौरान सभी लाभार्थियों को उनका मासिक राशन मिलेगा । इस ऐतिहासिक कदम से सरकार ने कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली है।

राष्ट्रपति ने कहा, 'हमारी अर्थव्यवस्था का आधार सुदृढ़ होने के कारण ही हम उपयोगी प्रयासों को शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य ऐसा वातावरण बनाना है जिससे सभी नागरिक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी वास्तविक क्षमताओं का उपयोग करें एवं उनका जीवन फले फूले।' मुर्मू ने कहा कि गणतंत्र का एक और वर्ष बीत चुका है तथा एक नया वर्ष शुरू हो रहा है..यह अभूतपूर्व परिवर्तन का दौर रहा है महामारी के प्रकोप से दुनिया कुछ ही दिनों में बदल गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जब भी हमें लगा कि हमने वायरस पर काबू पा लिया है तो वायरस फिर किसी विकृत रूप में वापस आ गया।

कोरोना से घबराना नहीं है- मुर्मू

मुर्मू ने कहा कि लेकिन अब इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यह समझ लिया है कि हमारा नेतृत्व कर रहे हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर, हमारे प्रशासक और कोरोना योद्धा.. वायरस से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने यह भी सीखा है कि हम अपनी सुरक्षा में कभी कमी नहीं आने देंगे तथा सतर्क रहेंगे। मुर्मू ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखना होगा हमें अपनी मूलभूत प्राथमिकताओं पर भी पुनर्विचार करना होगा परंपरागत जीवन मूल्यों के वैज्ञानिक आयामों को समझना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक बार फिर प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव और अनंत ब्रह्मांड के सम्मुख विनम्रता का भाव जागृत करना होगा।

इनसाइड

48 जवानों का 'हत्यारा' नक्सल कमांडर नवीन यादव ने किया सरेंडर! 25 लाख इनाम था घोषित

बिहार-झारखंड के सुरक्षा बलों के लिए राहत वाली खबर है। जानकारी के अनुसार, 25 लाख रुपये का इनामी नक्सल कमांडर नवीन यादव ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। नवीन के ऊपर 48 जवानों के हत्या का आरोप है।

रांची: झारखंड-बिहार में पुलिस और सुरक्षाबलों के 48 जवानों की हत्या के आरोपी इनामी नक्सली कमांडर नवीन यादव उर्फ सर्वजीत यादव अब पुलिस के कब्जे में है। खबर है कि उसने सरेंडर कर दिया है। उसपर सरकार ने 25 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। झारखंड के चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना क्षेत्र का बासखूटा गांव निवासी नवीन हाल तक माओवादियों के सुरक्षित गढ़ बूढ़ा पहाड़ में सक्रिय था। पुलिस और सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत तीन महीने पहले जब बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया, तभी से वह सरेंडर की कोशिश में लगा था। हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर नवीन यादव के सरेंडर की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरेंडर के बाद अज्ञात ठिकाने पर उससे पूछताछ की जा रही है।

नवीन माओवादियों की रीजनल कमेटी का मेंबर रहा है। उसका आतंक झारखंड के पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा और मध्य बिहार के औरंगाबाद, गया आदि जिलों में पिछले कई वर्षों से कायम था। इन इलाकों में पिछले एक दशक में नक्सलियों के ज्यादातर हमलों में वह शामिल रहा है। उसके ऊपर बिहार-झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जनवरी 2019 में नवीन यादव की पलामू के रेडमा में 18.5 एकड़, चतरा के प्रतापपुर में 12.78 एकड़ जमीन भी जब्त की थी। नवीन यादव पर 48 जवानों की हत्या का आरोप है। जून 2016 में बिहार के औरंगाबाद-गया सीमा पर बड़ा नक्सल हमला हुआ था, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में माओवादियों का नेतृत्व नवीन यादव ही कर रहा था। वह वर्ष 2013 में लातेहार के कटिया में सुरक्षा बलों पर हमले का भी मुख्य आरोपित है, जिसमें एक साथ 17 जवान शहीद हुए थे। 2011 में चतरा के तत्कालीन सांसद इंदर सिंह नामधारी के काफिले हमले में आठ जवान और जनवरी 2012 में गढ़वा के भंडरिया में नक्सल हमले में थाना प्रभारी समेत 13 जवान शहीद हुए थे। इन हमलों में भी नवीन यादव शामिल रहा है।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर मचा है घमासान, खिलाफत आंदोलन की कोख से निकली जामिया यूनिवर्सिटी का इतिहास जानिए

एनटीवी संवाददाता

जामिया विश्वविद्यालय देश के टॉप शिक्षण संस्थानों में से एक है। साल 1920 में अलीगढ़ से इसकी शुरुआत और 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने तक का सफर काफी दिलचस्प है। वहीं इस यूनिवर्सिटी का विवादों से भी नाता रहा है। आज हम इसके इतिहास पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे।

नई दिल्ली: देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक जामिया विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। यूं तो इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लोगों ने देश-विदेश में झंडे गाड़ रखे हैं लेकिन विवादों से भी इसका खूब नाता रहा है। साल 1920 को अलीगढ़ से शुरू हुई यह संस्था और बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की उपाधि पाने वाले इस विश्वविद्यालय की चर्चा एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो रही है। असल में गुजरात दंगे को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन आज वहां मौजूद छात्र संगठन ने शाम 6 बजे इसकी स्क्रीनिंग रखी थी। उससे पहले ही पुलिस फोर्स ने कुछ संगठन के कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। जामिया गेट न. 7 के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी जवान लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। खिलाफत और असहयोग आंदोलन की कोख से जन्मी जामिया के बार में हम स्थापना से लेकर विवाद समेत हर वो चीज बताएंगे।

गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री और चर्चा में जामिया

देश के सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक जामिया मिल्ली इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि उन्हें गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखनी है। इसके लिए आज शाम 6 बजे उसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग ऐसे समय पर रखी गई है जब केंद्र सरकार ने उसे बैन कर दिया है और जेएनयू में इसे लेकर पहले भी विवाद हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्ट विचारधारा वाले छात्रों ने बैन के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और डॉक्यूमेंट्री देखने वाले लोगों का आरोप है कि ABVP के छात्रों ने जबरन लाइट बंद की और पत्थरबाजी हुई।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर स्क्रीनिंग चाहते हैं छात्र

जेएनयू के बाद अब जामिया भी इस विवाद में कूद गया है। हालांकि स्क्रीनिंग के पहले ही पुलिसवालों ने कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद वहां मौजूद अन्य छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके बाद स्क्रीनिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं जामिया प्रशासन ने कहा कि बिना किसी पर्मिशन के कोई भी स्क्रीनिंग या छात्रों की बैठक नहीं होगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी आज डॉक्यूमेंट्री दिखाने की योजना है।

जामिया का इतिहास जान लीजिए

देश की आजादी के लिए चलाए जा रहे असहयोग और खिलाफत आंदोलन से जन्मे जामिया विश्वविद्यालय की स्थापना साल 1920 में अलीगढ़ में एक संस्थान के रूप में की गई थी। जामिया के संस्थापकों की लिस्ट में अली ब्रदर्स यानि मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर थे। वहीं इसकी आधारशिला स्वतंत्रता सेनानी रहे मौलाना मोहम्मद हसन ने रखी थी। आपको जानकर खुशी होगी कि जामिया की स्थापना में राष्टपिता महात्मा गांधी की भी अहम भूमिका थी। 1920 के बाद साल 1925 में इसे दिल्ली लाया गया। दिल्ली में इसे पहले करोल बाग शिफ्ट किया गया था। इसके बाद 1935 में इसे दिल्ली के ओखला लाया गया। 1936 में इसे नए कैंपस में शिफ्ट किया गया। यहीं जामिया के सभी संस्थान बनाए गए। साल 1988 में जामिया को संस्थान से विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया और तब से लेकर अबतक यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित है। जामिया मिल्लिया का अर्थ है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय।

विवादों से भी रहा है जामिया का नाता

एक वक्त बंद करने की भी आ गई थी नौबत क्या आपको पता है कि देशभर में अपनी शिक्षा के लिए मशहूर जामिया पर कभी आर्थिक तंगी भी आई थी। जी हां एक वक्त ऐसा भी आया था जब जामिया को बंद करने की नौबत आ गई थी। तब जामिया को इस तंगी से उबारने के लिए स्वयं महात्मा गांधी ने कमान संभाली थी। उन्होंने तब कहा था कि वह जामिया को बचाने के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने को भी तैयार हैं। जामिया के बारे में रवींद्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू ने भी तारीफ की थी। रवींद्र नाथ ने कहा कि यह भारत के सबसे प्रगितशील संस्थानों में से एक है वहीं सरोजनी नायडू ने कहा कि तिनका-तिनका जोड़कर और कई कुर्बानियों के बाद जामिया का निर्माण किया गया है।

सीएए-एनआरसी के विरोध में बुलंद हुई आवाज

जामिया विश्वविद्यालय जितना अपने एजुकेशन को लेकर मशहूर है वहीं दूसरी ओर विवादों से भी इसका गहरा नाता रहा है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए CAA-NRC कानून पर हुआ विवाद तो याद ही होगा। कई महीनों तक जामिया के पास शाहीन बाग की सड़क को जाम कर दिया गया था। एक विशेष समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। इस विरोध की आग जामिया तक भी पहुंची थी। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार सीएए-एनआरसी पर जैसे ही बिल लेकर आई। संसद से पैदा हुई विरोध के स्वर बाहर आ गए। 10 दिसंबर को आईडी ऑफ सिटीजनशिप पर चलने वाला यह कार्यक्रम दोपहर 2 बजे खत्म हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्र जामिया परिसर में जमा हुए। बिल को विरोध में नारेबाजी के बाद यह प्रदर्शन खत्म हो गया। 13 दिसंबर को संसद तक मार्च करने का निर्णय लिया गया। इसकी सूचना सोशल मीडिया पर पहले ही दे दी गई थी। 13 दिसंबर को तय समय के अनुसार, जामिया के छात्र हाथ में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए संसद की ओर बढ़ चले। कुछ दूर चलने के बाद छात्रों के समूह को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने रोक लिया और लाठीचार्ज किया। दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच इस झड़प में आरोप यह भी था कि उनके जवान भी घायल हुए हैं। इसमें छात्रों को हिरासत में लिया गया और कुछ घायल भी हुए। इसके बाद आपको पता ही है कि कैसे CAA-NRC के विरोध की यह आग दिल्ली से पूरे देश में फैल गई थी।

जामिया मे घुसी पुलिस और खूब हुआ हंगामा

सीएए-एनआरसी का विरोध जामिया कैंपस में खूब देखा गया था। 17 दिसंबर के आस-पास की बात है। जामिया के छात्रों पर आरोप था कि उन्होंने सीएए-एनआरसी के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया। पत्थरबाजी की गई। रविवार को पुलिस जामिया कैंपस के अंदर चली गई। छात्रों का कहना था कि पुलिस ने लाइब्रेरी के अंदर घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की। कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने बताया कि पुलिस ने बेरहमी से हमपर हमला किया। दरवाजे तोड़े, घुटने और सिर पर वार किए। छात्रों ने वीसी और पुलिस के खिलाफ खूब नारे लगाए गए थे। पूछा गया कि किसके आदेश पर पुलिस की एंट्री हुई थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि सीएए- एनआरसी के विरोध में छात्रों ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अब भी बवाल

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अब भी टेंशन जारी है। पुलिस का कहना है कि स्क्रीनिंग टाइम के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। वहीं छात्र संगठन के सदस्यों ने कहा कि जबतक हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा नहीं किया जाता तबतक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। हालांकि यह फैसला लिया है कि आज डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। SFI ने हिरासत में लिए छात्रों के बाद यह फैसला लिया गया है।

क्या दिग्विजय सिंह पर ऐक्शन लेगी कांग्रेस? 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी ने दिया जवाब

जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के बयान को हास्यास्पद बताया। साथ ही राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर ऐक्शन लिए जाने के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है तानाशाही नहीं।

झज्जर कोटली/जम्मू: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'सर्जिकल स्ट्राइक' पर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों को 'हास्यास्पद' करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सशस्त्र बल असाधारण रूप से अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणियों को लेकर मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी दिग्विजय सिंह के बयान से पूरी तरह से असहमत है।

राहुल गांधी ने यहां प्रेस वार्ता में कहा, 'ऐसे लोग हैं जो बातचीत के दौरान हास्यास्पद बातें कहते हैं। एक वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसा कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि उन्होंने हास्यास्पद बात कही है।' उन्होंने कहा, 'हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। अगर सेना कोई काम करती है तो उसे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं उनके बयान से पूरी तरह असहमत हूं और यह कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक स्थिति है कि यह दिग्विजय सिंह का निजी दृष्टिकोण है।'

दिग्विजय सिंह ने सोमवार को 'सर्जिकल स्ट्राइक' पर सवाल उठाया था और सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। जम्मू-कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए, सिंह ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के कर्मियों को हवाई मार्ग से श्रीनगर से दिल्ली भेजने के बल के अनुरोध पर सरकार सहमत नहीं हुई और 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमले में 40 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, 'वे 'सर्जिकल स्ट्राइक' की बात करते हैं। वे कई लोगों को मारने की बात करते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। वे झूठ के पुलिंदों के सहारे शासन कर रहे हैं।'

दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की जा रही कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है न कि पार्टी में तानाशाही है।

उन्होंने कहा, 'हम अपनी पार्टी को जबरदस्ती के सिद्धांत पर नहीं चलाते हैं। हम दिग्विजय सिंह के निजी विचारों की सराहना नहीं करते। लेकिन पार्टी के विचार दिग्विजय सिंह के विचारों से ऊपर हैं। पार्टी के भीतर बातचीत से विचार उत्पन्न होते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके विचार...वे विचार नहीं हैं जो पार्टी के केंद्र की ओर से रखे जाते हैं।'

उन्होंने कहा, 'हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सशस्त्र बल काम करते हैं। वे असाधारण रूप से अच्छा काम करते हैं। उन्हें किसी भी चीज का सबूत देने की जरूरत नहीं है।'

गांधी ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति है कि वार्ता हो। उन्होंने कहा, 'कई बार ऐसी बातचीत हो जाती है और अतिवादी विचार रखने वाले लोग अपनी बात कह देते हैं। हालांकि, बीजेपी और आरएसएस में बातचीत का कोई चलन नहीं है। एक बार वे कुछ भी तय कर लेते हैं और उसके बाद कोई बात नहीं कर सकता है।'